



जन जन की बात जन जन तक

साप्ताहिक

जन जन विचार



बहिर्जगत् कथा बहिर्जगत् माजरेन
जन जन विचार

WEEKLY TRILINGUAL NEWSPAPER

Language : Hindi, Assamese & English
WEBSITE : www.janjanvichar.in

VOICE OF ALL, FOR ALL

WEEKLY

JAN JAN VICHAR

RNI Regd No. ASMUL/25/A2367::Guwahati, Friday, 26 June 2026 :: Year-1 Vol-24 Issue-3 :: शुक्रवार | 26 जून 2026 | शक संवत् 1948 | ज्येष्ठ शुक्ल | द्वादशी :: पृष्ठ-20 | मूल्य - 15 रुपए

जन चिंतन
धनेश्वर चौधरी

फिर अनसुनी रह गई पूर्वोत्तर की आवाज

भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का सबसे बड़ा चेहरा यदि कोई राज्य है, तो वह असम है। वर्षों से कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर अब देश का अंतिम छोर नहीं, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया की ओर खुलने वाला भारत का प्रवेश द्वार है। लेकिन जब भारत-जापान शिखर सम्मेलन गुवाहाटी से हटकर नई दिल्ली पहुंच जाता है और जापान की प्रधानमंत्री का प्रस्तावित असम दौरा रद्द हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से कई सवाल उठते हैं।

आधिकारिक बयान में कारण 'अपरिहार्य परिस्थितियां' बताया गया है। लेकिन लोकतंत्र में केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं होता। जब किसी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में अंतिम समय पर बदलाव होता है, तो उसके कारणों पर शेष पृष्ठ 2 पर

असम नहीं आएंगी जपानी प्रधानमंत्री

पूर्वोत्तर की कूटनीतिक अहमियत पर विराम

जन जन विचार

... गुवाहाटी

भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के सबसे महत्वपूर्ण पड़वों में से एक माने जा रहे भारत-जापान शिखर सम्मेलन का गुवाहाटी से नई दिल्ली स्थानांतरण और जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची का प्रस्तावित असम दौरा रद्द होना कई सवाल खड़े कर गया है। आधिकारिक तौर पर इसे 'अपरिहार्य कारण' बताया गया है, लेकिन इस फैसले ने पूर्वोत्तर की रणनीतिक और कूटनीतिक भूमिका पर नई बहस छेड़ दी है।

पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में प्रस्तुत किया है। सड़क, रेल, हवाई संपर्क और व्यापारिक गलियारों पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। ऐसे में यदि भारत-जापान जैसे उच्चस्तरीय सम्मेलन



का आयोजन अंतिम समय में गुवाहाटी से हटाकर दिल्ली किया जाता है, तो यह केवल कार्यक्रम में बदलाव नहीं, बल्कि उस राजनीतिक संदेश को भी कमजोर करता है जिसे 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत लगातार प्रचारित किया जाता रहा है।

यह पहला अवसर नहीं है जब जापान के

शीर्ष नेतृत्व का असम दौरा अंतिम समय में रद्द हुआ हो। लगातार दूसरी बार ऐसा होने से यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या पूर्वोत्तर अब भी भारत की विदेश नीति के केंद्र में उतनी ही मजबूती से मौजूद है, जितना दावा किया जाता है, या फिर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए दिल्ली ही

अराजक ताकतें नहीं चाहती असम का विकास : पीयूष

जन जन विचार

... मोरीगांव

जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची का 1 जुलाई को प्रस्तावित असम दौरा रद्द होने के बाद राज्य की राजनीति तेज हो गई है। असम सरकार ने इस फैसले पर निराशा व्यक्त की है, जबकि राज्य के मंत्री पीयूष हजारिका ने दावा किया कि 'अराजक ताकतें असम का विकास नहीं चाहती' और इसी कारण ऐसा माहौल बना जिसने राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाया।

मोरीगांव में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में हजारिका ने कहा कि जापानी प्रधानमंत्री का प्रस्तावित दौरा राज्य के लिए निवेश और आर्थिक सहयोग की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा, 'अराजक ताकतें असम का विकास नहीं चाहती। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।' हालांकि,

उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि उनका इशारा किन समूहों या घटनाओं की ओर था और न ही अपने आरोप के समर्थन में कोई विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत किया।

जापानी प्रधानमंत्री का दौरा ऐसे समय रद्द हुआ है जब राज्य सरकार इस यात्रा को असम में विदेशी निवेश आकर्षित करने और भारत-जापान संबंधों को पूर्वोत्तर तक मजबूत करने के बड़े अवसर के रूप में देख रही थी। दौरे की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं।

दौरा रद्द होने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोगों ने हाल के विरोध प्रदर्शनों और गायक जुबिन गर्ग से जुड़े विवादों को इससे जोड़ने का प्रयास किया है। हालांकि, भारत सरकार, जापान सरकार या किसी आधिकारिक एजेंसी ने इन घटनाओं और दौरा रद्द होने के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं किया है।

GAURANSHI INDUSTRIES

Purity in Every Drop, Nature in Every Product.

100% NATURAL

- NO ADDITIVES
- BOOSTS IMMUNITY
- RICH IN ANTIOXIDANTS
- ECO FRIENDLY

PURE NATURAL GOODNESS		TEA	
NAME	MAKHANA (FOX NUT SUPERFOOD)	NAME	ASSAM CTC TEA
SIZE	200gm	NAME	ASSAM CTC TEA
		SIZE	100gm

HONEY

MORINGA HONEY		TULSI HONEY	
NAME	MORINGA HONEY	NAME	TULSI HONEY
SIZE	200gm	SIZE	200gm

MUSTARD HONEY		LITCHI HONEY		WILD FOREST HONEY	
NAME	MUSTARD HONEY	NAME	LITCHI HONEY	NAME	WILD FOREST HONEY
SIZE	200gm	SIZE	200gm	SIZE	200gm

RAW & UNPROCESSED

PURE & NATURAL

DIRECTLY FROM OUR FARMS

TRUSTED BY THOUSANDS

3rd Floor, IIT Road, Jayguru, Amingaon, Kamrup, Assam - 781031, India

Contact : +91-88224 20619

E-Mail : gauranshiind@gmail.com

www.gauranshiindustries.com

धन दिशा

छोटी आदत, बड़ी तनखाह से भी ज्यादा असरदार



हर हफ्ते, अखबार के इस कोने में हम पैसों की बात करेंगे - शेयर बाजार की मुश्किल भाषा में नहीं, बल्कि वैसे जैसे हम किसी पड़ोसी से चाय पर बात करते हैं। न मुश्किल शब्द, न डराने वाले आंकड़े। बस आसान बातें, जिन्हें आप उसी शाम से अपना सकें।

गुवाहाटी में मुझे सबसे ज्यादा यही सवाल पूछा जाता है, 'मेरी कमाई इतनी ज्यादा नहीं है, मैं बचत कैसे करूँ?'

सच्चाई यह है, जो शायद किसी ने आपको न बताई हो - बचत का संबंध आपकी कमाई से नहीं, बल्कि इस बात से है कि आप कितनी जल्दी और कितनी नियमितता से शुरुआत करते हैं। एक कहानी से समझते हैं।

रोबिन और विशाल, दोनों गुवाहाटी के, एक ही उम्र में नौकरी शुरू करते हैं। रोबिन ने 25 साल की उम्र से ही हर महीने 2,000 रुपये की एक एसआईपी (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) में निवेश शुरू कर दिया। विशाल टालता रहा - उसे लगा कि पहले

'बड़ी रकम' जोड़ ली जाए - और आखिरकार 35 साल की उम्र में 2,000 रुपये महीना शुरू किया।

55 साल की उम्र तक, मान लीजिए हर साल औसतन 10 प्रतिशत की बढ़त मिली, तो रोबिन का पैसा बढ़कर लगभग 38 लाख रुपये हो गया। विशाल, जिसने दस साल कम निवेश किया, उसके पास केवल लगभग 13 लाख रुपये ही जमा हुए - आधे से भी कम, भले ही उसकी कुल जमा राशि में फर्क इतना बड़ा नहीं था। असली फर्क केवल समय का था।

पैसा भी एक पेड़ की तरह बढ़ता है - जितनी जल्दी आप इसे लगाते हैं, बाद में उतनी ही बड़ी छाया मिलती है।

हर सफल बचतकर्ता की यही सीख है। एसआईपी शुरू करने के लिए बड़ी तनखाह की जरूरत नहीं - बहुत से लोग सिर्फ 500 रुपये महीने से शुरुआत करते हैं।

कोमल जैन
पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट

पृष्ठ 1 का शेषांश...

फिर अनसुनी रह गई पूर्वोत्तर की आवाज

स्पष्टता भी उतनी ही आवश्यक होती है।

दौरा रद्द होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। मंत्री पीयूष हजारिका ने हाल के विरोध प्रदर्शनों और बने माहौल की ओर संकेत करते हुए इसे एक संभावित कारण बताया। दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर भी यह दावा किया जा रहा है कि लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग से जुड़े विरोध प्रदर्शनों ने राज्य की छवि को प्रभावित किया। हालांकि, अब तक भारत सरकार, जापान सरकार या किसी आधिकारिक एजेंसी ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है। इसलिए इन्हें अंतिम सत्य मानना पत्रकारिता और लोकतंत्र-दोनों के साथ न्याय नहीं होगा।

लेकिन एक बड़ा प्रश्न अपनी जगह कायम है। यदि असम वास्तव में भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति का केंद्र है, तो ऐसे महत्वपूर्ण अवसर बार-बार राष्ट्रीय राजधानी

तक ही क्यों सीमित रह जाते हैं? क्या पूर्वोत्तर को केवल निवेश सम्मेलनों और चुनावी भाषणों में याद किया जाएगा, या वैश्विक कूटनीति का वास्तविक मंच भी यहीं बनेगा?

यह भी याद रखना होगा कि विरोध प्रदर्शन, किसी राजनीतिक दल का आंदोलन या सोशल मीडिया की बहस पूरे राज्य की पहचान नहीं होती। असम की पहचान उसकी संस्कृति, सामाजिक सौहार्द, आर्थिक संभावनाओं और जनता की मेहमाननवाजी से बनती है। किसी एक घटना के आधार पर पूरे प्रदेश का आकलन करना भी उचित नहीं होगा।

इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीति करने से अधिक आवश्यक है पारदर्शिता। यदि दौरा रद्द होने के पीछे सुरक्षा, कूटनीतिक या अन्य प्रशासनिक कारण थे, तो उन्हें स्पष्ट रूप से सामने लाया जाना चाहिए। अफवाहों की जगह तथ्य और आरोपों की जगह जवाब लोकतंत्र को मजबूत करते हैं।

असम नहीं आएंगी...

अंतिम विकल्प बनी रहेगी? विशेषज्ञों का मानना है कि

चढ़ावा विवाद : विहिप की साख पर संकट

जन जन विचार

...अयोध्या

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा और दानराशि प्रबंधन को लेकर उठे विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच और दर्ज प्राथमिकी के बाद विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की सक्रियता बढ़ गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और विहिप के शीर्ष पदाधिकारियों के बीच हुई बंद कमरे की बैठक ने संगठन और ट्रस्ट के भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है।

सूत्रों के अनुसार बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र, निर्माण प्रभारी गोपाल राव के अलावा विहिप के महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा, केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे और केंद्रीय सह-संगठन महामंत्री विनायक राव सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। हालांकि बैठक का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि चढ़ावा विवाद, एसआईटी जांच और उससे संगठन की छवि पर पड़ रहे प्रभाव पर विस्तार से



चर्चा हुई।

राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख रणनीतिकारों में रहे चंपत राय इस समय दान और चढ़ावा प्रबंधन को लेकर उठे सवालों के केंद्र में हैं। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में उनके खिलाफ लगातार

चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में विहिप के सामने सबसे बड़ी चुनौती मंदिर आंदोलन से जुड़ी अपनी विश्वसनीयता और संगठन की साख बनाए रखने की है।

हालांकि, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक स्वतंत्र और विधिक संस्था है। इसलिए विहिप के पास ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी को हटाने का अधिकार नहीं है। लेकिन चंपत राय स्वयं विहिप के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं। ऐसे में संगठन यदि आवश्यक समझे तो नैतिक आधार पर उन्हें कोई सलाह दे सकता है या अपने संगठनात्मक दायित्वों में परिवर्तन कर सकता है। राजनीतिक और सामाजिक हलकों में यह चर्चा भी तेज है कि कुछ ट्रस्टियों से त्यागपत्र मांगा जा सकता है।

साप्ताहिक राशिफल

26 जून से 2 जुलाई 2026 | विक्रम संवत् 2083-मास : ज्येष्ठ, पक्ष : शुक्ल, तिथि : द्वादशी

मेघ : रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी और मानसिक शांति बढ़ेगी। धन लाभ के संकेत हैं।

वृषभ : आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। नए काम, जिम्मेदारियाँ और सीखने के अवसर मिलेंगे। करियर में प्रगति संभव है, लेकिन काम का दबाव और थकान बढ़ सकती है।

मिथुन : नए काम, जिम्मेदारियाँ और सीखने के अवसर मिलेंगे। करियर में प्रगति संभव है, लेकिन काम का दबाव और थकान बढ़ सकती है।

कर्क : भावनात्मक उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है। काम सामान्य रहेगा लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है।

सिंह : मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन परिणाम संतोषजनक रहेंगे। काम का दबाव रहेगा, फिर भी आप अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभा पाएंगे।

कन्या : आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। आत्मविश्वास और सफलता का समय है।

तुला : इस सप्ताह चुनौतियाँ सामने आएंगी लेकिन आप उन्हें सफलतापूर्वक संभाल लेंगे।

वृश्चिक : रिश्तों में सुधार और सहयोग का समय है। पार्टनरशिप या टीमवर्क से लाभ मिलेगा।

धनु : नए अवसर मिलेंगे और करियर में आगे बढ़ने के संकेत हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक बदलाव होंगे। लेकिन लापरवाही से बचना जरूरी है।

मकर : स्थिर प्रगति का समय है। परिवार का सहयोग मिलेगा और निवेश से लाभ हो सकता है। सफलता धीरे-धीरे मिलेगी, इसलिए धैर्य बनाए रखें।

कुंभ : नए लोगों से संपर्क और नेटवर्किंग से फायदा मिलेगा। करियर में बदलाव के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय न लें।

मीन : इस सप्ताह काम में तेजी रहेगी और नए मौके मिल सकते हैं। आपकी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। लेकिन गुस्सा और जल्दबाजी रिश्तों और फैसलों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए संयम जरूरी है।

सप्ताह के पर्व/त्योहार

26 जून (शुक्रवार) : अंबुवासी निवृत्ति (सुबह 9.25 बजे)

27 जून (शनिवार) : शनि प्रदोष व्रत

29 जून (सोमवार) : संत कबीर जयंती

30 जून (मंगलवार) : गुरु हरगोविंद सिंह जयंती



● ज्योतिर्विद आचार्य अखिलेश्वर शुक्ल

भाग्योदय : पहला तल्ला, सेंट्रल प्लाजा, एमएस रोड
फैंसी बाजार, गुवाहाटी-781001 मो.-94350 40387

मेघालय में ब्लिंकिट की एंट्री पर रोक

जन जन विचार

... शिलांग

मेघालय में त्वरित ऑनलाइन आपूर्ति सेवा देने वाली कंपनी ब्लिंकिट की कारोबारी शुरुआत पर बड़ा झटका लगा है। खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (केएचएडीसी) ने कंपनी को अनिवार्य व्यापार लाइसेंस देने से इनकार कर दिया है। परिषद का कहना है कि कंपनी का कारोबार मॉडल शिलांग और आसपास के क्षेत्रों में संचालित 4,000 से अधिक स्थानीय किराना दुकानों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

केएचएडीसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य विंस्टन टोनी लिंगदोह ने स्पष्ट कहा कि परिषद ऐसे किसी भी मंच को व्यापार लाइसेंस नहीं देगी, जिसका व्यवसाय मॉडल स्थानीय व्यापारियों और स्वदेशी उद्यमियों के हितों के

4,000 से अधिक स्थानीय किराना दुकानों की सुरक्षा के लिए केएचएडीसी ने नहीं दिया व्यापार लाइसेंस



लिए चुनौती बनता हो। उन्होंने बताया कि ब्लिंकिट ने स्थानीय स्तर पर अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया था, लेकिन परिषद से आवश्यक व्यापार लाइसेंस नहीं लिया था।

सूत्रों के अनुसार, ब्लिंकिट ने शिलांग में प्रारंभिक स्तर पर सेवाएं शुरू कर सैकड़ों वितरण सहयोगियों को भी जोड़ा था, लेकिन आवश्यक अनुमति नहीं मिलने के कारण परिचालन रोकना पड़ा। परिषद ने यह भी बताया कि इससे पहले इसी

आधार पर अन्य त्वरित ऑनलाइन आपूर्ति कंपनियों को भी लाइसेंस देने से इनकार किया जा चुका है।

तेजी से बढ़ती त्वरित ऑनलाइन आपूर्ति सेवाओं ने देशभर में खुदरा व्यापार का स्वरूप बदल दिया है। भारी छूट, घर-घर आपूर्ति और

मोबाइल अनुप्रयोग आधारित सेवाओं के कारण छोटे दुकानदार प्रतिस्पर्धा का दबाव महसूस कर रहे हैं। मेघालय में परिषद ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आधुनिक व्यापार का स्वागत तभी होगा, जब उससे स्थानीय व्यापारियों के हित प्रभावित न हों।

मेघालय का यह निर्णय केवल एक कंपनी को लाइसेंस देने या न देने का मामला नहीं है, बल्कि यह प्रश्न है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्थानीय आजीविका के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। नई प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन सेवाएं विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन यदि उनके कारण हजारों छोटे व्यापारियों का रोजगार संकट में पड़ता है तो सरकारों और स्थानीय संस्थाओं के सामने संतुलित नीति बनाना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। आर्थिक विकास का सही मॉडल वही होगा जिसमें नवाचार भी आगे बढ़े और स्थानीय उद्यमियों की आजीविका भी सुरक्षित रहे।

नगा बंधकों की हत्या में समुदाय के कुछ लोगों की थी भूमिका

जन जन विचार

... इंपाल

मणिपुर में जारी जातीय संघर्ष के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। कुकी-जो परिषद (केजेडसी) ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि छह नगा बंधकों की हत्या में कुकी-जो समुदाय के कुछ लोगों की भूमिका थी। परिषद के अध्यक्ष हेनलियनथांग थांगलेट ने इस घटना को 'भावनाओं में हुई गंभीर भूल' बताते हुए पूरे समुदाय की ओर से सार्वजनिक माफी मांगी।

चुराचांदपुर में आयोजित

कुकी-जो परिषद ने पहली बार स्वीकारा, मांगी माफी

संवाददाता सम्मेलन में थांगलेट ने कहा कि इस घटना के लिए उन्हें गहरा खेद है, लेकिन पूरे कुकी-जो समुदाय को कुछ व्यक्तियों के कृत्य के आधार पर 'हिंसक' या 'अमानवीय' नहीं ठहराया जाना चाहिए। उनका कहना था कि हिंसा में उनका समुदाय भी भारी नुकसान झेल चुका है।

परिषद ने दावा किया कि लगातार हिंसक घटनाओं, दो कुकी युवकों की हत्या, तीन पादरियों पर हमले और अन्य घटनाओं के बाद माहौल अत्यधिक तनावपूर्ण हो गया था,

जिसके चलते यह दुखद घटना हुई। हालांकि, इन घटनाओं के क्रम, हताहतों की संख्या और विभिन्न संगठनों पर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। कुकी-जो परिषद ने केंद्र और मणिपुर सरकार से सभी हिंसक घटनाओं की निष्पक्ष जांच, प्रभावित गांवों तक खाद्यान्न और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, अवरुद्ध मार्गों को खोलने तथा नागरिकों पर हमलों के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिषद का आरोप है कि कुछ कुकी-जो गांवों में आवश्यक वस्तुओं की गंभीर

कमी बनी हुई है। किसी भी संघर्ष में अपनी समुदाय के लोगों द्वारा हुई हिंसा को स्वीकार करना आसान नहीं होता। कुकी-जो परिषद की सार्वजनिक माफी संवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा सकती है। लेकिन केवल माफी पर्याप्त नहीं होगी। मणिपुर में स्थायी शांति तभी संभव है जब प्रत्येक हिंसक घटना की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई हो और सभी समुदायों का विश्वास पुनः स्थापित किया जाए। शांति का मार्ग सत्य, न्याय और पारस्परिक विश्वास से होकर ही गुजरता है।

रोटरी क्लब ऑफ गुवाहाटी आइकॉन्स का स्थापना समारोह 28 को

गुवाहाटी। रोटरी क्लब ऑफ गुवाहाटी आइकॉन्स का छठा स्थापना समारोह 28 जून 2026 को शाम 7 बजे ए.टी. रोड स्थित विश्वरत्न होटल में आयोजित होगा। समारोह में दिसपुर के विधायक प्रद्युत बरदलै मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पूर्व जिला गवर्नर डॉ. एनएन दत्ता सम्मानित अतिथि तथा प्रभात केडिया स्थापना अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। प्रख्यात अभिनेत्री निशिता गोस्वामी और सहायक गवर्नर राजेश सिंह विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। आयोजन रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3240 के तत्वावधान में होगा।

बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर मंत्रियों ने लिया जायजा

गुवाहाटी। असम में बाढ़ की पहली लहर के तेज होने के बीच राज्य सरकार ने राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा तेज कर दी है। शिक्षा मंत्री रजो जेगू, जल संसाधन मंत्री सुशांत बरगोहाई और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री केशव महंत

ने धेमाजी, माजुली, लखीमपुर सहित कई बाढ़ एवं कटाव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मंत्रियों ने राहत शिविरों का निरीक्षण कर अधिकारियों को भोजन, पेयजल, दवाइयों और अन्य आवश्यक सामग्री की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित

करने के निर्देश दिए। सरकार ने कहा कि राहत कार्यों के साथ-साथ अब वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित दीर्घकालिक बाढ़ एवं कटाव नियंत्रण योजनाओं, मजबूत तटबंधों और स्थायी अवसंरचना के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।



संपादकीय

उस स्याह दिन की यादें

25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की सबसे विवादास्पद तिथियों में दर्ज है। इसी दिन घोषित आपातकाल ने नागरिक स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और राजनीतिक विरोध की आवाज पर व्यापक प्रतिबंध लगाए। हजारों राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लागू हुई और संविधान में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। यह दौर आज भी लोकतांत्रिक विमर्श का महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है।

इतिहास का उद्देश्य केवल अतीत को याद करना नहीं, बल्कि उससे सीख लेना भी है। इसलिए आपातकाल पर चर्चा किसी दल विशेष के समर्थन या विरोध का विषय नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह लोकतांत्रिक संस्थाओं, संवैधानिक मर्यादाओं और नागरिक अधिकारों की रक्षा के संकल्प का अवसर होना चाहिए।

यह भी उतना ही आवश्यक है कि इतिहास का मूल्यांकन तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर हो। किसी भी सरकार या राजनीतिक दल से ऊपर संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। सत्ता चाहे किसी की भी हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वायत्तता, स्वतंत्र प्रेस और विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र की आधारशिला हैं।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनता की जागरूकता है। जब नागरिक अपने अधिकारों और संविधान के प्रति सजग रहते हैं, तभी किसी भी प्रकार की निरंकुश प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है। आपातकाल का स्मरण अतीत की कटुता को दोहराने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए कि भारत में संविधान सर्वोपरि रहे और लोकतांत्रिक मूल्यों से कभी समझौता न हो।

स्मार्टफोन : सुविधा भी, चुनौती भी

स्मार्टफोन ने आधुनिक जीवन को अभूतपूर्व गति दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, संचार और रोजगार से लेकर सरकारी सेवाओं तक इसकी उपयोगिता निर्विवाद है। लेकिन जितनी तेजी से इसका उपयोग बढ़ा है, उतनी ही तेजी से इसके दुष्प्रभाव भी सामने आए हैं। विशेषकर बच्चों और युवाओं में अत्यधिक स्क्रीन समय, मानसिक तनाव, एकाग्रता में कमी, साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी, फर्जी समाचार और सामाजिक अलगाव जैसी समस्याएं गंभीर चिंता का विषय बन चुकी हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के विस्तार ने इस चुनौती को और जटिल बना दिया है। डीपफेक वीडियो, पहचान की चोरी और डिजिटल धोखाधड़ी जैसे अपराध अब स्मार्टफोन के माध्यम से आसानी से किए जा रहे हैं। इसलिए केवल तकनीक उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग का प्रशिक्षण देना भी आवश्यक है।

दुनिया के कई देशों ने स्कूलों में मोबाइल के उपयोग पर नियंत्रण और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने जैसे कदम उठाए हैं। भारत में भी समय आ गया है कि बच्चों के लिए स्क्रीन समय की सीमा, डिजिटल नैतिकता की शिक्षा और अभिभावकों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाए। तकनीक का विरोध समाधान नहीं है; समाधान है संयम, जागरूकता और जिम्मेदार उपयोग।

सना मलिक से कुछ सवाल

जन जन विचार

... नीरज कुमार दुबे

हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में समान नागरिक संहिता, तीन तलाक और मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा अचानक उस समय भड़क उठी जब सना मलिक ने खुलेआम कहा कि भारत में भी पाकिस्तान की तरह इस्लामिक कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने कुरान और मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए बहुविवाह और



तीन तलाक का समर्थन किया। यह बयान उस समय आया जब सदन में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और उनके साथ हो रहे अत्याचारों पर गंभीर चर्चा चल रही थी।

पूरा मामला भाजपा विधायक देवयानी फरांदे द्वारा नियम 105 के तहत प्रस्तुत ध्यानाकर्षण नोटिस से शुरू हुआ। उन्होंने सदन में कहा कि केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाया, लेकिन महाराष्ट्र में उसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम महिलाओं को आज भी बहुविवाह, घरेलू हिंसा और तलाक जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। देवयानी फरांदे ने बताया कि पिछले डेढ़ महीने में तीन मुस्लिम महिलाएं सहायता के लिए उनके पास पहुंचीं। किसी महिला को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई, तो किसी के पति ने उस पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर समान नागरिक संहिता कब लागू होगी और इसके लिए क्या विशेष कार्यबल बनाया जाएगा?

लेकिन मुस्लिम महिलाओं के दर्द और उनके अधिकारों की चर्चा के बीच सना मलिक ने जिस तरह पाकिस्तान और इस्लामिक कानून का समर्थन किया, उसने पूरे सदन का माहौल गरमा दिया। सना मलिक ने कहा कि पाकिस्तान ने कोई नया कानून नहीं बनाया, बल्कि कुरान में जो व्यवस्था दी गई है, उसका पालन किया है और भारत को भी पाकिस्तान की तरह कुरान के नियमों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बहुविवाह केवल मुस्लिम समाज में नहीं, बल्कि हर धर्म में होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कह दिया कि मुसलमानों में बहुविवाह का तरीका सिखाया गया है और उसका पालन होना चाहिए, इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए।

देखा जाए तो यह बयान केवल राजनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि यह उस मानसिकता को उजागर करता है जो भारत के संविधान से ऊपर मजहबी कानून को रखने की कोशिश करती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक महिला विधायक होकर भी सना मलिक को उन हजारों, लाखों मुस्लिम महिलाओं का दर्द क्यों नहीं दिखाई देता जो बहुविवाह और तीन तलाक जैसी प्रथाओं की वजह से वर्षों तक प्रताड़ना झेलती रही हैं। देश में कई ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं जहां कई पत्नियां रखने वाले पुरुषों पर महिलाओं के शोषण,

मारपीट और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगे। इसके बावजूद बहुविवाह को जायज ठहराना आखिर किस मानसिकता का परिचायक है?

उधर, सना मलिक के बयान पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने सना मलिक के बयान पर कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि चर्चा का विषय तीन तलाक कानून का क्रियान्वयन है, पाकिस्तान या मजहबी परंपराएं नहीं। उन्होंने साफ कहा कि यह देश संविधान से चलता है, कुरान से नहीं। यहां पाकिस्तान और धार्मिक कानूनों की वकालत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाजपा और शिवसेना के विधायकों ने भी सना मलिक के बयान का जोरदार विरोध किया।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि महायुति सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। उन्होंने उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लागू समान नागरिक संहिता कानून में बहुविवाह पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है और उल्लंघन करने वालों के लिए सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि सना मलिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक की बेटी हैं। नवाब मलिक का नाम पहले भी गंभीर विवादों में आ चुका है। वर्ष 2022 में प्रवर्तन निदेशालय को उनके अंडरवर्ल्ड डॉन दारुद इब्राहिम गिरोह से संबंधों के सबूत मिलने का दावा किया गया था।

बहरहाल, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में बैठे बाकी दल केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण इस बयान पर चुप हैं? क्या संविधान की शपथ लेने वाले जनप्रतिनिधियों को खुलेआम पाकिस्तान और इस्लामिक कानून की पैरवी करने की छूट मिलनी चाहिए? यह केवल राजनीतिक बहस नहीं, बल्कि भारत की संवैधानिक पहचान और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा हुआ सवाल है।

सना मलिक ने कहा कि पाकिस्तान ने कोई नया कानून नहीं बनाया, बल्कि कुरान में जो व्यवस्था दी गई है, उसका पालन किया है और भारत को भी पाकिस्तान की तरह कुरान के नियमों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बहुविवाह केवल मुस्लिम समाज में नहीं, बल्कि हर धर्म में होता है।

होर्मुज पर ईरान का सख्त संदेश

‘तेहरान की मंजूरी के बिना नहीं होगी आवाजाही’, चेतावनी के बाद कई जहाज लौटे

जन जन विचार

...तेहरान/मस्कट

दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरान ने नया सख्त रुख अपनाया है। ईरान की इस्लामिक रिवायतशास्त्री गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की नौसेना ने जहाजों को रेडियो संदेश भेजकर कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में होर्मुज से गुजरने वाले पोत केवल ईरान के समन्वय और उसके निर्देशित मार्गों के अनुसार ही आवाजाही करें। चेतावनी के बाद

फारस की खाड़ी में प्रतीक्षा कर रहे कई जहाजों के वापस लौटने की खबरें सामने आई हैं।

आईआरजीसी ने ओमान द्वारा प्रस्तावित अस्थायी समुद्री गलियारों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए उन्हें जोखिमपूर्ण बताया और कहा कि निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों को ‘भारी कीमत’ चुकानी पड़ सकती है।

दूसरी ओर, ओमान ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का समर्थन करते हुए स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य होर्मुज में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन सुनिश्चित करना है। ओमान ने



अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुरूप नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति

डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज समुद्री मार्ग बिना किसी शुल्क या प्रतिबंध के खुला रहेगा।

हालांकि, ईरान की चेतावनी और

अमेरिकी दावों के बीच स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

दुनिया की नजर होर्मुज पर क्यों ?

होर्मुज जलडमरूमध्य से विश्व के समुद्री मार्ग से होने वाले कच्चे तेल और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस के बड़े हिस्से की आपूर्ति होती है। इस मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, तेल की कीमतों, समुद्री व्यापार और आयात-निर्यात पर पड़ सकता है। भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों के लिए भी यह घटनाक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज

अयोध्या। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर रामजन्मभूमि कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इस मामले में टिन्नु यादव और अनुकल्प मिश्रा सहित आठ नामजद तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि विशेष जांच दल (एसआईटी) की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और शासन की संस्तुति के बाद यह कार्रवाई की गई। राज्य सरकार ने मामले में सख्त रुख अपनाया है तथा जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई और संभावित गिरफ्तारियों की तैयारी की जा रही है।

व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर पर लगी पाबंदियां हटीं

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने व्यावसायिक उपयोग वाले पैक्ड एलपीजी सिलिंडरों की आपूर्ति पर लगाई गई अस्थायी पाबंदियां हटा दी हैं। सरकार का यह निर्णय पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति सामान्य होने के बाद लिया गया है। इसके साथ ही होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की आपूर्ति पूर्व व्यवस्था के अनुसार बहाल कर दी गई है। इस बीच भारत और ईरान ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ईरान के पेट्रोलियम मंत्री मोहसिन पाकनेजाद के बीच हुई बैठक में तेल और गैस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर विचार-विमर्श हुआ।

कनिष्क बम विस्फोट में खालिस्तानी आतंकवादियों की भूमिका मानी

ओटावा/नई दिल्ली। कनाडा की खुफिया एजेंसी सीएसआईएस ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि वर्ष 1985 में एअर इंडिया फ्लाइट 182 (कनिष्क) में हुए बम विस्फोट के पीछे कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी आतंकवादियों का हाथ था। इस भीषण आतंकवादी हमले में विमान में सवार सभी 329 लोगों की मृत्यु हो गई थी। आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति में जारी संदेश में एजेंसी ने इस घटना को कनाडा के इतिहास का सबसे घातक आतंकवादी हमला बताया। सीएसआईएस ने कहा कि यह हमला देश की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।

एनकाउंटर का सच : कानून की गोली या सत्ता की गोली ?

लोकतंत्र में पुलिस को बंदूक इसलिए नहीं दी जाती कि वह न्यायालय की भूमिका निभाए, बल्कि इसलिए दी जाती है कि वह कानून के दायरे में रहकर अपराध पर नियंत्रण रखे। बिहार के भोजपुर में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवाल केवल एक व्यक्ति की मौत का मामला नहीं हैं, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र में कानून के शासन की परीक्षा भी है।

पुलिस का दावा है कि भरत तिवारी ने फायरिंग की और आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई। यदि ऐसा है तो जांच में यह स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन यदि आत्मरक्षा के नाम पर जरूरत से अधिक बल प्रयोग हुआ है, तो यह भी सामने आना चाहिए। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मृतक के शरीर में कई गोलियां लगने की बात सामने आई है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस की अपनी एफआईआर और घटनाक्रम के बीच कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता दिखाई देती है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि हमारे समाज में अब एनकाउंटर को न्याय का पर्याय बना दिया गया है। भीड़ अदालतों की धीमी प्रक्रिया से निराश होकर गोली को फैसला मानने लगी है। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। यदि किसी व्यक्ति के अपराधी होने का निर्णय पुलिस ही करेगी, पुलिस ही सजा सुनाएगी और पुलिस ही गोली चलाएगी, तो फिर संविधान, अदालत और न्याय व्यवस्था का क्या अर्थ रह जाएगा ?

यह भी सच है कि पुलिसकर्मी अक्सर जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। अपराधियों की गोली का सामना करते हैं। लेकिन इसी कारण उनसे अधिक जवाबदेही की अपेक्षा भी की जाती है। कानून का रक्षक कानून से ऊपर नहीं हो सकता।



भरत तिवारी निर्दोष था या अपराधी, इसका फैसला अदालत करती। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई? क्या वास्तव में आत्मरक्षा की स्थिति थी? क्या सभी वैकल्पिक उपाय समाप्त हो चुके थे? क्या गोली चलाना अंतिम विकल्प था? और यदि था, तो कितनी गोली आवश्यक थी?

इन सवालों का जवाब न तो सोशल मीडिया की अदालत दे सकती है और न ही राजनीतिक बयानबाजी। इसका उत्तर केवल निष्पक्ष न्यायिक जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक बैलिस्टिक जांच से ही मिल सकता है।

जनतंत्र में पुलिस की वर्दी पर जनता का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होती है। यदि किसी एनकाउंटर पर संदेह पैदा होता है, तो उस संदेह को दबाने की नहीं, दूर करने की आवश्यकता होती है। पुलिस को भी जांच से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्य यदि उसके पक्ष में है तो वही उसकी सबसे बड़ी ढाल बनेगा।

भरत तिवारी एनकाउंटर का सच चाहे जो हो, एक बात स्पष्ट है—कानून के राज में गोली नहीं, साक्ष्य बोलने चाहिए। अन्यथा कल कोई भी नागरिक यह विश्वास खो देगा कि न्याय अदालतों में मिलता है।

प्रश्न केवल भरत तिवारी की मौत का नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या भारत में कानून अभी भी सर्वोपरि है, या फिर बंदूक की नली ही न्याय का नया रास्ता बनती जा रही है?

बदलती पाठ्यपुस्तकें, बदलता भारत

नौवीं की सामाजिक विज्ञान पुस्तक में व्यापक परिवर्तन
अब छात्र पढ़ेंगे आपातकाल, उद्यमिता और समकालीन भारत

जन जन विचार
... नई दिल्ली

शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय करने वाला सबसे प्रभावशाली साधन भी है। यही कारण है कि जब विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों में बड़े बदलाव होते हैं, तो उनकी चर्चा केवल शिक्षा जगत तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाज और राजनीति में भी उसका व्यापक प्रभाव दिखाई देता है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा नौवीं की सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक जारी की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-2023 के अनुरूप तैयार इस पुस्तक में विषय-वस्तु, संरचना और अध्ययन पद्धति—तीनों स्तरों पर महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं।

सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन यह है कि पहली बार विद्यार्थियों को 1975 के आपातकाल का अध्ययन कराया जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था के इस महत्वपूर्ण अध्याय

को विद्यालयी शिक्षा में शामिल करना इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों को भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों, नागरिक अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों को समझने का अवसर मिलेगा।

चार पुस्तकों का एकीकरण

अब तक इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र अलग-अलग पुस्तकों में पढ़ाए जाते थे। नई व्यवस्था में इन चारों विषयों को एक ही सामाजिक विज्ञान पुस्तक में समाहित किया गया है। इससे विषयों के बीच समन्वित समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है और विद्यार्थियों का अध्ययन अधिक सरल बनाने की कोशिश की गई है।

क्या बदला, क्या हटाया गया ?

नई पुस्तक से फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, नाजीवाद और हिटलर का उदय, वन समाज और उपनिवेशवाद तथा आधुनिक विश्व में पशुपालक जैसे अध्याय हटा दिए गए हैं।

भूगोल में भारत की भौतिक संरचना, प्राकृतिक वनस्पति और

वन्यजीव जैसे विषयों को एकीकृत किया गया है, जबकि जनसंख्या संबंधी अध्याय को हटाया गया है। इसके स्थान पर पंजाब की बाढ़ (2025), कार्बन पदचिह्न, आपदा प्रबंधन और पर्यावरणीय चुनौतियों जैसे समकालीन विषय जोड़े गए हैं।

अर्थशास्त्र में गरीबी, खाद्य सुरक्षा और पालमपुर गांव की कहानी जैसे अध्यायों के स्थान पर स्वरोजगार, उद्यमिता, नवाचार और नवप्रारंभ (स्टार्टअप) जैसी अवधारणाओं को महत्व दिया गया है, ताकि विद्यार्थी रोजगार खोजने के साथ-साथ रोजगार सृजन की सोच भी विकसित कर सकें।

इतिहास की नई दृष्टि

नई पुस्तक की शुरुआत आदिमानव, सिंधु-सरस्वती (हड़प्पा) सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, महिलाओं की भूमिका और प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था से होती है। इससे भारतीय इतिहास को प्रारंभिक आधार के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास स्पष्ट दिखाई देता है।

बहस भी होगी, संवाद भी

पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन सदैव

बहस का विषय रहे हैं। एक पक्ष इसे समयानुकूल और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन मानता है, तो दूसरा पक्ष आशंका व्यक्त करता है कि कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन सीमित हो सकता है।

यह आवश्यक है कि शिक्षा का उद्देश्य किसी विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में तर्कशीलता, संवैधानिक मूल्यों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संतुलित ऐतिहासिक समझ विकसित करना हो।

पाठ्यपुस्तकें केवल परीक्षा पास करने का साधन नहीं होतीं; वे आने वाली पीढ़ी को सोच और दृष्टि का निर्माण करती हैं। समय के साथ पाठ्यक्रम बदलना स्वाभाविक है, परंतु परिवर्तन का आधार व्यापकता, तथ्यपरकता और संतुलन होना चाहिए। विद्यार्थियों को भारत के गौरवशाली अतीत के साथ-साथ लोकतंत्र की चुनौतियों, विश्व इतिहास, सामाजिक परिवर्तन और समकालीन समस्याओं का भी समुचित ज्ञान मिले—यही एक सशक्त और जागरूक नागरिक समाज की पहचान है।

आईआईटी गुवाहाटी में
बिना गेट एमटेक में
प्रवेश का अवसर

गुवाहाटी। भारतीय

प्रौद्योगिकी संस्थान

(आईआईटी) गुवाहाटी ने बाढ़ एवं जल संसाधन प्रबंधन विषय में दो वर्षीय एमटेक पाठ्यक्रम के दूसरे बैच के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पाठ्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रवेश के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) का अंक अनिवार्य नहीं है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि कक्षाएं 10 अगस्त से प्रारंभ होंगी।

प्रवेश लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थी के पास सिविल इंजीनियरिंग, कृषि अभियांत्रिकी अथवा संबंधित विषय में स्नातक उपाधि, न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक तथा जल संसाधन क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है। यह पाठ्यक्रम मिश्रित (ऑनलाइन एवं परिसर) अध्ययन प्रणाली पर आधारित है और इसका उद्देश्य बाढ़ प्रबंधन, नदी बेसिन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन योजना तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण जैसे क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञ तैयार करना है।

एसबीआई में विधि अधिकारियों के 49 पदों पर भर्ती

जन जन विचार
... नई दिल्ली

देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारी (विधि) भर्ती 2026-27 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। भर्ती अभियान के तहत सहायक प्रबंधक (विधि) तथा उप प्रबंधक (विधि) के कुल 49 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो चुकी है और 14 जुलाई 2026 तक चलेगी।

इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (एलएलबी) की उपाधि होना अनिवार्य है। पांच वर्षीय समेकित विधि पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जा सकती है।

अनुभव भी अनिवार्य

सहायक प्रबंधक (विधि) पद के लिए अभ्यर्थी के पास बार

परिषद में पंजीकरण के बाद कम से कम दो वर्ष का अधिवक्ता अथवा बैंक के विधि विभाग में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

उप प्रबंधक (विधि) पद के लिए न्यूनतम चार वर्ष का संबंधित अनुभव आवश्यक है। अनुभव की गणना बार परिषद में पंजीकरण के बाद की जाएगी।

आवेदन शुल्क

सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

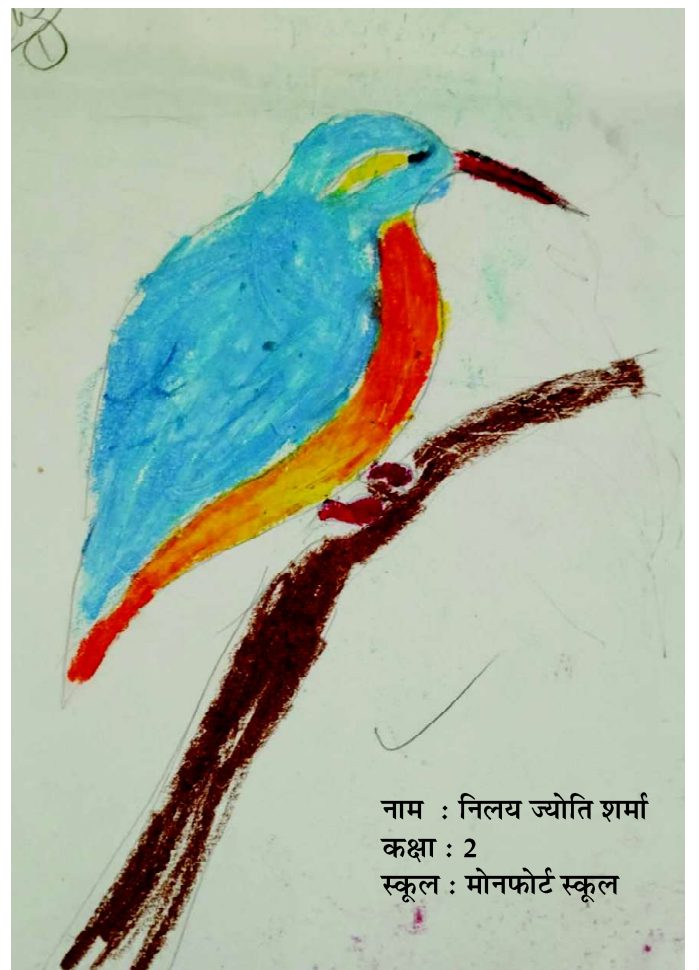
आवेदन कैसे करें ?

इच्छुक अभ्यर्थी भारतीय स्टेट बैंक के आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करें, आवश्यक विवरण भरें, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र, छायाचित्र एवं हस्ताक्षर अपलोड करें और निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन पूर्ण करें।

बैंक चिकित्सा अधिकारी के 35 पदों पर भर्ती

नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने बैंक चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ-द्वितीय) के 35 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो चुकी है और 14 जुलाई 2026 तक चलेगी। अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस की उपाधि तथा आवश्यक कार्यानुभव होना अनिवार्य है। एमबीबीएस अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम पांच वर्ष तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा उपाधिधारकों के लिए तीन वर्ष का अनुभव आवश्यक है। चयन शॉर्टलिस्टिंग, साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर होगा। अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है।

बाल चित्रकार



नाम : निलय ज्योति शर्मा
कक्षा : 2
स्कूल : मोनफोर्ट स्कूल

बेलफास्ट में 'नए भारत' की पहली परीक्षा

जन जन विचार
...सपोर्ट्स डेस्क

भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी-20 श्रृंखला का आगाज 26 जून से बेलफास्ट में होगा। श्रृंखला जितनी श्रेयस अय्यर की कप्तानी के लिए अहम है, उतनी ही 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के संभावित अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण को लेकर भी चर्चा में है। यदि उन्हें अंतिम एकादश में मौका मिलता है, तो वे भारत की ओर से सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं।

श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में भारतीय टीम युवा जोश और अनुभवी खिलाड़ियों के संतुलन के साथ मैदान में उतरेगी। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी बल्लेबाजी को मजबूती देंगे, जबकि अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और रवि बिश्नोई पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी होगी।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीम प्रबंधन वैभव सूर्यवंशी पर भरोसा जताएगा। यदि उन्हें मौका मिलता है, तो शीर्ष क्रम में बदलाव लगभग तय माना जा रहा है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि वैभव और अभिषेक शर्मा की आक्रामक जोड़ी भारत



को तेज शुरुआत दे सकती है।

संभावित भारतीय प्लेइंग-11

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह।

नजर इन तीन खिलाड़ियों पर

वैभव सूर्यवंशी : यदि मौका मिला तो सबसे कम उम्र में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड बना सकते हैं।

श्रेयस अय्यर : कप्तान के रूप में पहली

टी-20 श्रृंखला, नेतृत्व और बल्लेबाजी दोनों पर नजर रहेगी।

अभिषेक शर्मा : विस्फोटक शुरुआत देने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी।

यह श्रृंखला केवल दो मैचों की नहीं, बल्कि भारतीय टी-20 टीम की नई दिशा की परीक्षा भी है। चयनकर्ताओं ने युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताकर साफ संकेत दिया है कि अब भविष्य की टीम तैयार की जा रही है। यदि वैभव सूर्यवंशी को पदार्पण का अवसर मिलता है, तो यह भारतीय क्रिकेट में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है।

वैभव के लिए इंग्लैंड में
अलग ड्रेसिंग रूम

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। महज 15 वर्ष की उम्र में भारतीय टीम में चयनित इस युवा बल्लेबाज के सामने इंग्लैंड दौरे पर एक अनोखी स्थिति आने वाली है। यदि उन्हें आयरलैंड के खिलाफ पहले टी-20 मैच में मौका मिलता है, तो वे भारत के सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं।

हालांकि, उनकी उम्र के कारण इंग्लैंड में उन्हें टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने की अनुमति नहीं होगी। आईसीसी और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के सुरक्षा नियमों के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए अलग चेंजिंग रूम की व्यवस्था अनिवार्य है।

इसी कारण हर मैच स्थल पर वैभव के लिए अलग ड्रेसिंग रूम तैयार किया जाएगा। उनके माता-पिता भी पूरे दौरे में उनके साथ रहेंगे और टीम के होटल में ठहरेंगे, ताकि उन्हें पारिवारिक सहयोग और सुरक्षा मिल सके।

विश्व कप का सपना और भारतीय फुटबॉल की हकीकत

जन जन विचार
...सपोर्ट्स डेस्क

फीफा विश्व कप 2026 का रोमांच पूरी दुनिया में छाया हुआ है। भारत के करोड़ों फुटबॉल प्रेमी भी अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील और जर्मनी जैसी टीमों का खेल देखकर यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर भारत कब विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर पहुंचेगा? यही सवाल हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के अनुभवी गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने भी एक अलग दृष्टिकोण से उठाया।

गुरप्रीत सिंह संधू ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि भारतीय फुटबॉल प्रेमी गलत सवाल पूछ रहे हैं। उनके अनुसार असली प्रश्न यह नहीं है कि भारत फीफा विश्व कप के लिए क्यों क्वालिफाई नहीं करता, बल्कि यह है कि भारत एएफसी एशियन कप में लगातार और प्रभावशाली प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाता।

संधू का मानना है कि विश्व कप तक पहुंचने का रास्ता एशियाई फुटबॉल में मजबूत पहचान बनाने से होकर गुजरता है। उन्होंने लिखा कि यदि भारत को विश्व कप में खेलना है तो पहले उसे नियमित रूप से एएफसी एशियन कप में पहुंचना होगा और फिर वहां नॉकआउट चरण तक लगातार पहुंचने की क्षमता विकसित करनी होगी।

उनकी बात पूरी तरह तर्कसंगत प्रतीत होती है। एशिया की जिन टीमों ने विश्व फुटबॉल में अपनी पहचान बनाई है, उनमें

गुरप्रीत सिंह संधू ने उठाया बड़ा सवाल



जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सउदी अरबिया प्रमुख हैं। इन देशों ने पहले महाद्वीपीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत की और फिर विश्व कप में नियमित भागीदारी सुनिश्चित की।

दुर्भाग्यवश भारत का हालिया प्रदर्शन

निराशाजनक रहा है। भारत 2027 एएफसी एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा। क्वालिफायर में भारतीय टीम अपने समूह में सबसे नीचे रही। इससे पहले 2023 एशियन कप में भी भारतीय टीम एक भी गोल किए बिना तीनों मैच हार गई थी।

ये आंकड़े बताते हैं कि भारत और एशिया की शीर्ष टीमों के बीच अभी भी बड़ा अंतर मौजूद है।

भारतीय फुटबॉल की चुनौतियां केवल मैदान तक सीमित नहीं हैं। जमीनी स्तर पर प्रतिभा विकास, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी, कोचिंग व्यवस्था, युवा अकादमियों का अभाव और प्रशासनिक समस्याएं लंबे समय से चर्चा का विषय रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में शामिल होने के बावजूद भारत की फीफा रैंकिंग 138 के आसपास होना चिंताजनक है।

भारत ने बाइचुंग भूटिया, सुनील छेत्री और आईएम विजयन जैसे महान खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रतिभा को राष्ट्रीय सफलता में बदलने के लिए मजबूत फुटबॉल ढांचे की आवश्यकता होती है।

गुरप्रीत सिंह संधू का संदेश भारतीय फुटबॉल के लिए एक चेतावनी भी है और मार्गदर्शन भी। विश्व कप का सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मजबूत नींव जरूरी है। जब तक भारत एशियाई फुटबॉल में लगातार प्रतिस्पर्धी नहीं बनता, तब तक विश्व कप की मंजिल दूर ही रहेगी।

भारत को अब विश्व कप की चर्चा से आगे बढ़कर उस मूल प्रश्न का उत्तर खोजना होगा जिसे गुरप्रीत ने उठाया है—आखिर भारतीय फुटबॉल एशिया में अपनी स्थायी पहचान क्यों नहीं बना पा रहा? इसी सवाल का समाधान भारत के फुटबॉल भविष्य को नई दिशा दे सकता है।

20 साल बाद लौटेंगे 'थ्री इंडियट्स'

जन जन विचार
...एंटरटेनमेंट डेस्क

साल 2009 में आई फिल्म '3 इंडियट्स' सिर्फ एक सुपरहिट फिल्म नहीं थी, बल्कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली एक सामाजिक क्रांति बन गई थी। 'ऑल इज वेल' का संदेश आज भी करोड़ों लोगों की जुबान पर है। अब लगभग दो दशक बाद निर्देशक राजकुमार हिरानी ने संकेत दिया है कि फिल्म का सीक्वल 20 साल आगे की कहानी लेकर आएगा। यह खबर उन करोड़ों दर्शकों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है, जिन्होंने रैंचो, फरहान और राजू के साथ अपने सपनों को जीया था।

अब कॉलेज नहीं, जिंदगी की असली परीक्षा

पहली फिल्म में तीन दोस्त इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे। वे अंकों की दौड़, करियर के दबाव और परिवार की अपेक्षाओं से जूझ रहे थे। लेकिन नया सीक्वल उन किरदारों को जीवन के बिल्कुल नए मोड़ पर दिखाएगा।

अब वे नौकरी, परिवार, बच्चों की पढ़ाई, आर्थिक जिम्मेदारियों और बदलती सामाजिक परिस्थितियों का सामना कर रहे होंगे। सवाल यह होगा कि क्या रैंचो आज भी वही आदर्शवादी सोच रखता है? क्या फरहान अपने सपनों के साथ खुश है? क्या राजू ने जीवन की चुनौतियों पर पूरी तरह जीत हासिल कर ली है?

क्या बदली होगी शिक्षा व्यवस्था?

पिछले 20 वर्षों में भारत की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। डिजिटल शिक्षा,

क्या बदल चुका होगा रैंचो, फरहान और राजू का संसार?



ऑनलाइन क्लास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप संस्कृति और नई शिक्षा नीति जैसे विषय अब युवाओं की जिंदगी का हिस्सा हैं।

ऐसे में सीक्वल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह आज के दौर के छात्रों और अभिभावकों के सामने मौजूद नई समस्याओं को कितनी ईमानदारी से प्रस्तुत करता है। यदि पहली फिल्म ने 'डिग्री बनाम प्रतिभा' की बहस छेड़ी थी, तो दूसरी फिल्म शायद 'तकनीक बनाम मानवीय संवेदना' का प्रश्न उठाए।

बदल चुका है समाज बदल चुकी है सोच

आज सफलता का पैमाना केवल नौकरी नहीं, बल्कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता, स्टार्टअप, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत पहचान भी बन चुका है। मानसिक तनाव, वर्क-लाइफ बैलेंस और डिजिटल जीवन जैसी चुनौतियां

पहले से कहीं अधिक गंभीर हो गई हैं।

ऐसे समय में '3 इंडियट्स' का सीक्वल केवल पुरानी यादों का सहारा लेकर सफल नहीं हो सकता। उसे नए भारत की नई पीढ़ी की वास्तविकताओं को भी उतनी ही मजबूती से सामने लाना होगा।

पुरानी स्टारकास्ट, नई जिम्मेदारी

आमिर खान, आर. माधवन, शरमन जोशी, करीना कपूर खान, बोमन ईरानी और मोना सिंह जैसे कलाकारों ने पहली फिल्म को अमर बना दिया था। दर्शकों की अपेक्षा होगी कि यदि यही कलाकार दोबारा लौटते हैं तो वे केवल पुराने किरदारों की पुनरावृत्ति न करें, बल्कि उनके जीवन की नई यात्रा को भी उतनी ही विश्वसनीयता से प्रस्तुत करें।

सिर्फ मनोरंजन नहीं समाज का आईना

'3 इंडियट्स' ने यह साबित किया था कि सिनेमा केवल

मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण भी हो सकता है। यदि सीक्वल भी उसी संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ आज की पीढ़ी की चुनौतियों को सामने लाता है, तो यह फिल्म एक बार फिर समाज में महत्वपूर्ण बहस को जन्म दे सकती है।

बीस वर्षों बाद लौट रही '3 इंडियट्स' केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक पीढ़ी की यादों की वापसी है। लेकिन समय बदल चुका है और दर्शकों की अपेक्षाएं भी। अब देखना होगा कि राजकुमार हिरानी एक बार फिर मनोरंजन के साथ समाज को आईना दिखाने में कितने सफल होते हैं। यदि कहानी आज के भारत के बदलते सपनों, शिक्षा और जीवन की वास्तविकताओं को ईमानदारी से छू पाती है, तो यह सीक्वल भी इतिहास रच सकता है।

बरसात में फर्नीचर की सुरक्षा थोड़ी सावधानी लाखों की बचत

मानसून की फुहारें जहां गर्मी से राहत देती हैं, वहीं घर के महंगे फर्नीचर के लिए बड़ी चुनौती भी बन जाती हैं। हवा में बढ़ी नमी लकड़ी को फूलाने, फंगस पैदा करने और कपड़े वाले सोफों में सीलन व बदबू का कारण बनती है। यदि समय रहते देखभाल न की जाए तो वर्षों की मेहनत से खरीदा गया फर्नीचर कुछ ही महीनों में खराब हो सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, सबसे पहले फर्नीचर को दीवार से कम-से-कम 6-7 इंच दूर रखें, ताकि हवा का प्रवाह बना रहे। लकड़ी के फर्नीचर पर समय-समय पर वैक्स या अच्छी गुणवत्ता की पॉलिश की परत चढ़ाने से नमी का असर कम होता है। घर में पर्याप्त वेंटिलेशन बनाए रखें और बारिश रुकने पर खिड़कियां खोलकर ताजी हवा आने दें।

बरसात में फर्नीचर की नियमित सफाई भी बेहद जरूरी है। सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से धूल साफ करें और गीले कपड़े, रेनकोट या छाते को कभी भी सोफे या लकड़ी के फर्नीचर पर न रखें। कपड़े वाले सोफों और गद्दों की वैक्यूम क्लीनिंग करें तथा धूप निकलने पर उन्हें कुछ देर अवश्य सुखाएं।

याद रखें, फर्नीचर केवल घर की शोभा नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण निवेश भी है। थोड़ी-सी सावधानी और नियमित देखभाल से आप अपने महंगे फर्नीचर को वर्षों तक नया और सुरक्षित बनाए रख सकते हैं।

कसाब को फांसी तक पहुंचाने वाले वकील की कहानी लेकर आ रहे राजकुमार राव

जन जन विचार
...एंटरटेनमेंट डेस्क

उज्ज्वल निकम, देश के एक जाने-माने वकील थे जिन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य आरोपी और इकलौते जिंदा पकड़े गए आतंकवादी को फांसी तक पहुंचाने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी।

अब उज्ज्वल निकम और केस की कहानी को बड़े पर्दे पर अभिनेता राजकुमार राव लाने जा रहे हैं। एक्टर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'प्रहार' का टीजर आखिरकार जारी कर दिया गया

'प्रहार' का टीजर आउट



है। फिल्म में राजकुमार उज्ज्वल निकम की भूमिका में दमदार लग रहे हैं।

प्रहार का टीजर आउट

फिल्म का टीजर उज्ज्वल निकम से शुरू होता है जो कोर्ट में अजमल कसाब को फांसी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। फिल्म में उनका लुक सबसे दमदार है। वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर के लुकस भी धमाकेदार हैं। करीब 2 मिनट के इस टीजर ने दर्शकों का दिल खुश कर दिया।

क्या है फिल्म की कहानी?

इस फिल्म में राजकुमार पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम का रोल निभा रहे हैं, जिन्होंने मुंबई में 26/11 के हमलों के मुख्य आरोपी अजमल कसाब को सजा दिलाने में मदद की थी। फिल्म में ललित ने कसाब का रोल किया है। टीजर में उस रात के परेशान करने वाले दृश्य भी दिखाए गए हैं जब कसाब ने मुंबई में आम लोगों पर गोलियां चलाई थीं। यह फिल्म उस भयानक घटना को उस ट्रायल के नजरिए से दिखाती है जिसमें कसाब को दोषी ठहराया गया था।

कब रिलीज होगी प्रहार? सच्ची घटनाओं पर आधारित राजकुमार राव की फिल्म 'प्रहार' 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अगस्त के महीने में और भी फिल्में आ रही हैं। 26 अगस्त को 'टॉक्सिक' और 28 अगस्त को श्रद्धा कपूर की 'ईठा' और सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'वन' आ रही है। 20 दिन में राजकुमार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है, यह रिलीज के बाद ही मालूम पड़ेगा।

অসম : উদ্যোগ, শিক্ষা আৰু পৰ্যটন খণ্ডলৈ নতুন দিশ

জন জন বিচাৰ

...শুৱাহাটী

অসমক অধিক উদ্যোগমুখী, বিনিয়োগ-অনুকূল আৰু পৰ্যটন-বান্ধৱ ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য কেবিনেটে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত বৈঠকত কৃষিভূমিৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন, ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান, গৃহ-আতিথ্য ব্যৱস্থা, সৌৰ শক্তি আৰু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ সম্পৰ্কীয় একাধিক সংস্কাৰমূলক সিদ্ধান্ত অনুমোদন কৰা হয়।

ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগলৈ ডাঙৰ সকাহ

কেবিনেটে অনুমোদন জনোৱা অসম ভূমি পুনঃশ্ৰেণীবিভাজন আৰু শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তনসহ হস্তান্তৰ সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬ অনুসৰি এতিয়াৰ পৰা ক্ষুদ্ৰ, কুটীৰ, খাদী আৰু সহযোগী উদ্যোগ অথবা সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প স্থাপনৰ বাবে কৃষিভূমিৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত জিলা আয়ুক্তৰ পূৰ্বানুমতিৰ প্ৰয়োজন নাথাকিব। এই ব্যৱস্থাই উদ্যোগ স্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়া অধিক সহজ আৰু দ্ৰুত কৰি তুলিব।

ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান স্থাপন সহজ

কেবিনেটৰ যুগান্তকাৰী সিদ্ধান্ত



কেবিনেটে অসম ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৭ সংশোধন কৰি পৰ্যটন ভূমি আৰু আমানত পুঁজিৰ বাধ্যবাধকতা শিথিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। একে সময়তে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়

স্থাপনৰ নিয়মো সহজ কৰা হৈছে, যাতে ৰাজ্যত অধিক শিক্ষানুষ্ঠান গঢ়ি উঠে আৰু শিক্ষাৰ সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

পৰ্যটনত একক-জাননী ব্যৱস্থা গৃহ-আতিথ্য আৰু আন

ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আৰু সৌৰ শক্তি প্ৰকল্পৰ বাবে কৃষিভূমিৰ স্বয়ংক্ৰিয় শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন-

ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যালয় আৰু গৃহ-আতিথ্য ব্যৱস্থাত নিয়ম শিথিল

আবাসিক পৰ্যটন প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে একক-জাননী পঞ্জীয়ন ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰা হৈছে। লগতে পঞ্জীয়নৰ ম্যাদ প্ৰতি তিনি বছৰৰ অন্তৰে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে নবীকৰণৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে। চৰকাৰৰ মতে, ইয়াৰ ফলত গ্ৰাম্য পৰ্যটন আৰু আত্মনিয়োজিত উদ্যোগে অধিক গতি লাভ কৰিব।

চাহ উদ্যোগ আৰু ন্যায্যমূল্যৰ দোকানলৈ গুৰুত্ব

অসম চাহ নিগমৰ বিষয়াসকলৰ স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ আঁচনি ৰূপায়ণৰ বাবে ৯.৭৫ কোটি টকা অনুমোদন কৰা হৈছে। লগতে ৰাজ্যৰ সকলো ন্যায্যমূল্যৰ দোকানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ ম্যাদ ৩১ ডিচেম্বৰ, ২০২৬লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে, যাতে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা

আইনৰ হি তাধিকাৰীসকলক নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে খাদ্যশস্য যোগান ধৰিব পৰা যায়।

সুযোগৰ সৈতে দায়িত্বও বৃদ্ধি

কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তসমূহে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ, নবীকৰণযোগ্য শক্তি, শিক্ষা আৰু পৰ্যটন খণ্ডত নতুন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। প্ৰশাসনিক জটিলতা হ্ৰাস পালে যুৱ উদ্যোগী আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে অধিক লাভৱান হব।

কিন্তু কৃষিভূমিৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন সহজ কৰাৰ ফলত কৃষিযোগ্য ভূমি সংৰক্ষণ, পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু পৰিকল্পিত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ তদাৰকিৰো প্ৰয়োজন থাকিব।

উন্নয়নৰ গতি বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপসমূহ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। কিন্তু যিকোনো সংস্কাৰৰ সফলতা নিৰ্ভৰ কৰে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা আৰু সঠিক ৰূপায়ণৰ ওপৰত। কৃষক, উদ্যোগী, শিক্ষাৰ্থী আৰু সাধাৰণ জনতাৰ স্বার্থ সুৰক্ষিত ৰাখি এই নীতিসমূহ কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰিলেহে অসমৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নত ইয়াৰ বাস্তৱ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হব।

বাজেটৰ সফলতা কেৱল ঘোষণা নহয়, টকাৰ সঠিক ব্যৱহাৰত

জন জন বিচাৰ

...শুৱাহাটী

অসমৰ নতুন চৰকাৰৰ প্ৰথমখন বাজেট অহা ১০ জুলাইত বিধানসভাত দাখিল হ'ব। বাজেটক



কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক আলোচনা। এইবাৰ বিত্তমন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষ্য ঘোষণা কৰিছে- বাজেটত আৱণ্টিত ধনৰ প্ৰায় ১০০ শতাংশ ব্যৱহাৰ নিশ্চিত কৰা।

এই ঘোষণা কেৱল এটা প্ৰশাসনিক লক্ষ্য নহয়; ই চৰকাৰৰ উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গীৰো পৰিচয় বহন কৰে। বহু সময়ত দেখা যায় যে বাজেটত বৃহৎ অংকৰ ধন আৱণ্টন কৰা হয় যদিও বহু শেষত তাৰ এটা অংশ ব্যয় নোহোৱাকৈ উভতি যায়। ফলত বহু উন্নয়নমূলক আঁচনি অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰয়।

ৰাজ্য চৰকাৰে পথ-ঘাট, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, কৃষি, পানীয় জল, নিয়োগ আৰু

সামাজিক সুৰক্ষাৰ বাবে আৱণ্টন কৰা ধন যদি সময়মতে ব্যয় হয়, তেন্তে সাধাৰণ নাগৰিকেই তাৰ প্ৰত্যক্ষ সুফল লাভ কৰে। সেয়েহে ধন আৱণ্টনতকৈ

১১ পৃষ্ঠাত

IND365অসমne

ৰ বাবে

নগাঁও, জাগীৰোড, হোজাই

লংকা, কঠিয়াতলি, কামপুৰ

বৰপেটা, নলবাৰী

ৰ পৰা সংবাদদাতা বিচৰা হৈছে

১৫০খন আসন, অথচ ৪০০ৰো অধিক অনুত্তীৰ্ণ শিক্ষার্থী

জন জন বিচাৰ
...গুৱাহাটী

এবাৰ ভুল হল, কিন্তু দ্বিতীয়বাৰ সুযোগ পামনে?—এই প্ৰশ্নই এতিয়া তাদিত কৰিছে লামডিং মহাবিদ্যালয়ৰ শতাধিক অনুত্তীৰ্ণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীক।

অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অনুত্তীৰ্ণ শিক্ষার্থীসকলক পুনৰ অধ্যয়নৰ সুযোগ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে পুনৰ নামভৰ্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। কিন্তু লামডিং মহাবিদ্যালয়ত এই পদক্ষেপেই নতুন সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে।

সমস্যা কত?

চলিত বৰ্ষত লামডিং মহাবিদ্যালয়ৰ ৪০০ৰো অধিক শিক্ষার্থী উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অনুত্তীৰ্ণ হৈছিল। কিন্তু শিক্ষা বিভাগে পুনৰ নামভৰ্তিৰ বাবে মাত্ৰ ১৫০খন আসন অনুমোদন দিয়াত প্ৰায় ২৫০ৰো অধিক শিক্ষার্থী নামভৰ্তিৰ সুযোগৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ আশংকাত আছে।

ফলস্বৰূপে শিক্ষার্থী আৰু অভিভাৱকৰ মাজত গভীৰ অনিশ্চয়তা আৰু উদ্বেগৰ সৃষ্টি

লামডিং মহাবিদ্যালয়ত পুনৰ নামভৰ্তিক লৈ অনিশ্চয়তাৰ ছাঁ



হৈছে।

দ্বিতীয় সুযোগ কেৱল
কাগজতে নেকি?

শিক্ষার্থীসকলে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শিক্ষামন্ত্রী ডঃ বণুজ পেগুলাৰ আবেদন জনাই পুনৰ নামভৰ্তিৰ আসন সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। তেওঁলোকৰ যুক্তি স্পষ্ট—এবাৰ ব্যৰ্থ হোৱাটোৱেই জীৱনৰ অন্ত নহয়।

চৰকাৰে যদি পুনৰ সুযোগ দিয়াৰ কথা কয়, তেন্তে সেই সুযোগ সকলো যোগ্য শিক্ষার্থীৰ বাবে উপলব্ধ হব লাগিব।

অভিভাৱকৰ উদ্বেগ

অভিভাৱকসকলেও কয় যে বহু পৰিয়ালৰ বাবে দূৰৱৰ্তী মহাবিদ্যালয়ত সন্তানক পঢ়িবলৈ পঠোৱাটো আৰ্থিকভাৱে সম্ভৱ নহয়। গতিকে লামডিং মহাবিদ্যালয়তে

অধিক আসনৰ ব্যৱস্থা কৰাটোৱেই অধিক বাস্তৱসন্মত সমাধান।

শিক্ষানীতিৰ উদ্দেশ্য বনাম বাস্তৱতা

ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি-২০২০-এ শিক্ষার্থীক অধিক নমনীয়তা, পুনৰ সুযোগ আৰু অন্তৰ্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। কিন্তু পুনৰ নামভৰ্তিৰ আসন সীমিত থাকিলে সেই নীতিৰ

উদ্দেশ্য বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত অপূৰ্ণ হৈ ৰয়। শিক্ষাবিদসকলৰ মতে, অনুত্তীৰ্ণ শিক্ষার্থীক পুনৰ শিক্ষাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰাটো কেৱল একাডেমিক বিষয় নহয়; ই ড্ৰপআউট হ্ৰাস আৰু ভৱিষ্যৎ কৰ্মসংস্থাপনৰ সৈতেও জড়িত।

প্ৰশাসনৰ পৰা আশাবাদী
পদক্ষেপৰ অপেক্ষা

এই সমস্যা কেৱল লামডিংৰ নহয়; ৰাজ্যৰ আন বহু শিক্ষানুষ্ঠানতো এনে পৰিস্থিতি সৃষ্টি হব পাৰে। সেয়েহে শিক্ষা বিভাগে বাস্তৱ পৰিস্থিতি মূল্যায়ন কৰি প্ৰয়োজন অনুসৰি পুনৰ নামভৰ্তিৰ আসন বৃদ্ধি বা বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে বহু শিক্ষার্থীৰ শৈক্ষিক জীৱন পুনৰ গঢ়ি তোলাৰ সুযোগ সৃষ্টি হব।

শিক্ষা হৈছে শান্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা নহয়, জীৱন গঢ়াৰ এক সুযোগ। অনুত্তীৰ্ণ হোৱাটো ব্যৰ্থতাৰ শেষ অধ্যায় নহয়; সঠিক দিশনিৰ্দেশনা আৰু পুনৰ সুযোগে এজন শিক্ষার্থীৰ ভৱিষ্যৎ সলনি কৰিব পাৰে। সেয়েহে চৰকাৰ, শিক্ষা বিভাগ আৰু মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই শিক্ষার্থীৰ স্বাৰ্থক অগ্ৰাধিকাৰ দি সমস্যাটোৰ মানৱীয় আৰু বাস্তৱসন্মত সমাধান বিচৰাটো সময়ৰ দাবী।

অৰুণাচলত আকস্মিক বানঃ উদ্ধাৰ আৰু পথ পুনৰ নিৰ্মাণ তৎপৰতা বৃদ্ধি

জন জন বিচাৰ
...ইটানগৰ

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেইবাখনো জিলাত আকস্মিক বান, ভূমিস্থলন আৰু পথ ধ্বংসৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা দুৰ্যোগৰ পিছত উদ্ধাৰ আৰু পুনৰুদ্ধাৰ অভিযান অধিক তীব্ৰ কৰা হৈছে। সীমান্ত পথ সংস্থা, ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰতিক্ৰিয়া বাহিনী আৰু জিলা প্ৰশাসনে যৌথভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত পথ মুকলি আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা পুনৰ স্বাভাৱিক কৰাৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছে।

পতিন-পোছা পথত আঠটা বৃহৎ বাধাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈছে। পতিন-লিচি আৰু পোছা-পতিন পথ বৰ্তমান যান-বাহন চলাচলৰ অনুপযোগী হৈ আছে। প্ৰশাসনে জনোৱা মতে, ক্ষয়-ক্ষতি অধিক হোৱাৰ বাবে পথ সম্পূৰ্ণৰূপে পুনৰ মুকলি কৰিবলৈ



আৰু তিনিৰ পৰা চাৰি দিন সময় লাগিব পাৰে।

উদ্ধাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিবলৈ এছডিআৰএফ আৰু জিলা আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত দল মোতায়েন কৰা হৈছে। বৰ্তমানো নিখোজ হৈ থকা চাৰিজন লোকৰ সন্ধান অব্যাহত আছে। ইতিমধ্যে এজন সংকটজনক ৰোগীক হেলিকপ্টাৰে জিৰোৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰাৰ লগতে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ ভাৰতীয়

বায়ুসেনাৰ সহায়ত সুৰক্ষিতভাৱে স্থানান্তৰ কৰা হৈছে।

ইয়াৰ উপৰিও, স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলত সাময়িকভাৱে খোৱাপানীৰ যোগান পুনৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে। প্ৰশাসনে জনোৱা মতে, নতুন পিটাপুল অঞ্চলত অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থা অতি সোনকালে আংশিকভাৱে পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে কাম চলি আছে।

এই সপ্তাহৰ ৰাশিফল

২৫-০৬-২০২৬ পৰা ০১-০৭-২০২৬লৈ

মেঘঃ ঘৰুৱা সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পাব। বন্ধুদ্ৰৰ পৰা সহায়-সহযোগিতা লাভ কৰিব। ব্যৱসায়-বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক।

বৃষঃ কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। মানসিক অস্থিৰতা অনুভৱ কৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত সময় শুভ।

মিথুনঃ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো শুভ। সন্তানৰ স্বাস্থ্যজৰ প্ৰতি বিশেষ নজৰ দিয়ক। কৰ্মক্ষেত্ৰত সুনাম বৃদ্ধি পাব।

কৰ্কটঃ মানসিক সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পাব। লেন-দেনৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। স্বাস্থ্যজৰ প্ৰতি যত্ন লওক।

সিংহঃ আকস্মিক ব্যয় বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কৰ্মক্ষেত্ৰ শুভ। বিদ্যাৰ্থীসকলে অধিক মনোযোগী হোৱাৰ প্ৰয়োজন।

কন্যাঃ মানসিক উদ্বিগ্নতা থাকিব পাৰে। ঘৰুৱা বাদ-বিবাদৰ পৰা আঁতৰি থাকক। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ফল লাভ কৰিব।

তুলাঃ অদৰকাৰী বাদ-বিবাদৰ পৰা বিৰত থাকক। মানসিক সুখ-শান্তি বজাই থাকিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে সময় শুভ।

বৃশ্চিকঃ ৰাশিঃ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। স্বাস্থ্যজৰ ক্ষেত্ৰত শুভ।

ধনুঃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক সচেতন হওক। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে সময় শুভ। কৰ্মক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক।

মকৰঃ দৈনন্দিন কাম-কাজত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। মানসিক সুখ-শান্তি বজাই থাকিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে শুভ সময়।

কুম্ভঃ মানসিক উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি পাব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত অদৰকাৰী বাদ-বিবাদৰ পৰা আঁতৰি থাকক। আৰ্থিক দিশ শুভ।

মীনঃ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে সময় শুভ। অদৰকাৰী খৰচৰ পৰা সাৱধান হওক। অদৰকাৰী বাদ-বিবাদৰ পৰা বিৰত থাকক।

-হিতেন শৰ্মা শাস্ত্ৰী

অধ্যাপক, বিশ্ব জ্যোতিষ বিদ্যাৰ্থী, অসম শাখা
যোগাযোগ: ৯৮৫৪০২৬৭৭৯

কৃষকৰ আয় বৃদ্ধি নোহোৱালৈকে অসমৰ দ্ৰুত উন্নয়ন অসম্ভৱ : পীযুষ

কৃষিখণ্ডলৈ নতুন দিশৰ আহ্বান: গৱেষণা, জলসিঞ্চন আৰু বৈজ্ঞানিক কৃষিত গুৰুত্ব



জন জন বিচাৰ

...গুৱাহাটী

অসমৰ ৭০ শতাংশতকৈ অধিক লোক কৃষিৰ সৈতে জড়িত, তথাপিও ৰাজ্যখন আজিও খাদ্যশস্য আৰু আন বহু কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ বাবে বহিঃৰাজ্যৰ ওপৰত যথেষ্ট নিৰ্ভৰশীল। এই বাস্তৱতাক উল্লেখ কৰি কৃষিমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই স্পষ্ট ভাষাত কয়- কৃষকৰ আয় উল্লেখযোগ্যভাৱে বৃদ্ধি নোহোৱালৈকে অসমৰ দ্ৰুত উন্নয়ন সম্ভৱ নহয়।

খানাপাৰাস্থ অসম প্ৰশাসনিক কৰ্মচাৰী মহাবিদ্যালয়ত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কৃষি বিভাগৰ যৌথ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৃষিখণ্ড বিষয়ক মত-বিনিময় সভাত ভাষণ দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, কৃষকৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত কৰাটো চৰকাৰ,

গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আৰু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ অন্যতম দায়িত্ব।

জলসিঞ্চনৰ অভাৱ-উন্নয়নৰ

আটাইতকৈ ডাঙৰ বাধা

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, অসমত বৰ্তমান মাত্ৰ ২৪ শতাংশ কৃষিভূমিতেই জলসিঞ্চনৰ সুবিধা আছে। ইয়াৰ বিপৰীতে মধ্যপ্ৰদেশত এই হাৰ প্ৰায় ৭৫ শতাংশ আৰু পঞ্জাবত প্ৰায় ১০০ শতাংশ। জলসিঞ্চনৰ এই পিছপৰাতাই উৎপাদন বৃদ্ধি আৰু বহুফচলী কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত অন্যতম বাধা হৈ আছে।

গৱেষণা আৰু প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব

কৃষি খণ্ডৰ স্থায়ী উন্নয়নৰ বাবে নতুন প্ৰযুক্তি, উন্নত বীজ, আধুনিক কৃষি পদ্ধতি আৰু বজাৰমুখী উৎপাদনৰ ওপৰত অধিক গৱেষণাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত

গুৰুত্ব আৰোপ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তেওঁৰ মতে, কৃষি, পশুপালন আৰু মীন পালন বিভাগৰ মাজত অধিক সমন্বয় গঢ়ি তুলিব পাৰিলেহে কৃষকৰ আয় বৃদ্ধি সম্ভৱ।

সভাত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচার্য ডঃ দীপজ্যোতি ৰাজখোৱাই অসমৰ কৃষিক জাতীয় অগ্ৰাধিকাৰ আৰু বিশ্ব কৃষিৰ ধাৰাৰ সৈতে খাপ খুৱাই ব্যৱসায়িকভাৱে লাভজনক কৰি তোলাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে।

অসমৰ অৰ্থনীতিৰ ভেটি আজিও কৃষি। কিন্তু জলসিঞ্চনৰ সীমিত ব্যৱস্থা, বৈজ্ঞানিক কৃষিৰ অভাৱ, সংৰক্ষণ আৰু বজাৰ ব্যৱস্থাৰ দুৰ্বলতাই কৃষকক প্ৰাপ্য লাভৰ পৰা বঞ্চিত কৰি আহিছে। কেৱল উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিলেই যথেষ্ট নহয়; কৃষকৰ আয়, কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ মূল্য সংযোজন, সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা আৰু বজাৰ সংযোগ শক্তিশালী কৰাটোও সমানে প্ৰয়োজন।

অসমৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ চাবিকাঠি কৃষিৰ হাততেই আছে। কৃষক লাভৱান হলে গাঁও সমৃদ্ধ হব, গাঁও সমৃদ্ধ হলে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিও শক্তিশালী হব। সেয়েহে কৃষি খণ্ডত গৱেষণা, জলসিঞ্চন, আধুনিক প্ৰযুক্তি, বজাৰ ব্যৱস্থা আৰু কৃষক-অনুকূল নীতিত অধিক বিনিয়োগেই সময়ৰ দাবী।

ৰোহাত উন্নতমানৰ ধানৰ বীজ বিতৰণ

জন জন বিচাৰ

...ৰোহা

নগাঁও জিলা কৃষি বিভাগৰ অধীনস্থ ৰোহা মহকুমা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত শতাধিক কৃষকৰ মাজত উন্নতমানৰ ধানৰ বীজ বিতৰণ কৰা হয়। অনুষ্ঠানত ৬১ নং ৰোহা সমষ্টিৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে আনুষ্ঠানিকভাৱে চি আৰ ধান আৰু ৰঞ্জিত চাব-ৰ জাতৰ

ধানৰ বীজ বিতৰণ কৰি কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে।

সভাত ভাষণ দি বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কৃষিমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্য চৰকাৰে কৃষকৰ উন্নয়নৰ বাবে একাধিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁ আগন্তুক দিনত কৃষকসকলক ৯০ শতাংশ ৰাজসাহায্যত ট্ৰেণ্ডাৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে ৰোহাত ধান

ক্ৰয় কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হব বুলি ঘোষণা কৰে।

অনুষ্ঠানত নগাঁও জিলা কৃষি বিষয়া নিখিল নাৰায়ণ বৰুৱাই কৃষকসকলক কৃষি বিভাগৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰি ভূমি পঞ্জীয়ন সম্পন্ন কৰি চৰকাৰী সুবিধা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনায়। সভাত ৰোহা সহকাৰী আয়ুক্ত ডঃ অংকিতা বৰা, পৌৰপতি বন্তী হাজৰিকা আৰু শতাধিক কৃষক উপস্থিত থাকে।

পৃষ্ঠাৰ ৯ পৰা

বাজেটৰ সফলতা কেৱল ঘোষণা নহয়...

ধনৰ ফলপ্ৰসূ ব্যৱহাৰ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ।

অৰ্থনীতিবিদসকলৰ মতে, ১০০ শতাংশ ধন ব্যয় কৰাটোৱেই সফলতা নহয়। ধন কিমান স্বচ্ছভাৱে, কিমান সময়মতে আৰু কিমান ফলপ্ৰসূভাৱে ব্যৱহাৰ হ'ল-সেয়াই মূল বিচাৰ্য বিষয়। বহু ক্ষেত্ৰত বছৰ শেষৰ ফালে তাড়াহুড়াকৈ

ধন ব্যয় কৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন হয়। এনে প্ৰৱণতা ৰোধ কৰাটো সমানেই জৰুৰী। চৰকাৰে এইবাৰ আন্তঃগাঁথনি, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিয়োগ সৃষ্টি, সামাজিক কল্যাণ আৰু জনসেৱাৰ মান উন্নয়নক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ ইংগিত দিছে। বিশেষকৈ বানপ্ৰৱণ অসমত বান নিয়ন্ত্ৰণ, গাঁও সংযোগী পথ, চিকিৎসা ব্যৱস্থা আৰু যুৱক-যুৱতীৰ কৰ্মসংস্থাপনক অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে জনসাধাৰণে।

বাজেটৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ১৩টা গুৰুত্বপূৰ্ণ

বিভাগৰ সৈতে দীঘলীয়া পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে। ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল প্ৰতিটো বিভাগৰ কাম-কাজ মূল্যায়ন কৰি বাস্তৱমুখী আৰু জনমুখী বাজেট প্ৰস্তুত কৰা। অসমবাসীয়ে এইবাৰৰ বাজেটৰ পৰা কেৱল নতুন ঘোষণা নহয়, পূৰ্বৰ আঁচনিসমূহৰ সফল ৰূপায়ণো আশা কৰিছে। উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বাস্তৱায়িত হ'ব তেতিয়াহে, যেতিয়া আৱণ্টিত প্ৰতিটো টকা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা আৰু সময়মতে ব্যয় হ'ব।



নাজিৰাৰ ঢেকেৰী গাঁৱত প্ৰায় ১২ ফুট দীঘল এটা অজগৰ উদ্ধাৰ কৰি বন বিভাগৰ হাতত চমজাই দিছে সাপ-মিত্ৰ পল্লৱ বৰপাত্ৰগোহাঁয়ে। চিকিৎসাৰ পিছত অজগৰটো লকুৱা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এৰি দিয়া হয়।

মেধাৰী ছাত্ৰীক শৈক্ষিক বঁটা প্ৰদান

নাজিৰা। নাজিৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ত মেধাৰী ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্মৃতি শৈক্ষিক বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান গাভীৰপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হয়। কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজিত অনুষ্ঠানত বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ তুলসী কোঁৱৰে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে আৰু জ্যেষ্ঠ শিক্ষক ৰুহিত চাবুকধৰাই সভাপতিত্ব কৰে।

অনুষ্ঠানত অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক বিজয় চন্দ্ৰ বৰা আৰু নাজিৰা-শিমলুগুৰি উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ ডঃ অজয়লাল বৰুৱাই ছাত্ৰীসকলক অনুপ্ৰেৰণামূলক ভাষণ আগবঢ়ায়। বিভিন্ন স্মৃতি শৈক্ষিক বঁটা নুৰজাহান বেগম, অদিতি কেওট, চাদ্ৰিকা আখতাৰ ৰহমান, ময়ূৰাঙ্গী বৰুৱা আৰু জাহ্নৱী বুঢ়াগোহাঁইকে ধৰি কেইবাগৰাকীও মেধাৰী ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰা হয়। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ এই প্ৰচেষ্টাই ছাত্ৰীসকলক অধ্যয়ন আৰু সমাজসেৱাৰ দিশত অধিক অনুপ্রাণিত কৰিব বুলি উপস্থিত ৰাইজে মত প্ৰকাশ কৰে।

দেহ ব্যৱসায়ৰ অভিযোগ, আৰক্ষীৰ অভিযান

শিলচৰ। শিলচৰ চহৰৰ দ্বিতীয় লিংক ৰোডৰ ১৪ নম্বৰ লেনস্থিত এখন বাসগৃহত দেহ ব্যৱসায় চলি থকাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই একাধিক লোকক আটক কৰে।

ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয়। ক্ষুদ্ৰ স্থানীয় বাসিন্দাসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অভিযোগ কৰে যে, উক্ত স্থানত দীৰ্ঘদিন ধৰি অবৈধ কাৰ্যকলাপ চলি আহিলেও ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সময়মতে ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল।

স্থানীয় ৰাইজে অঞ্চলটোত নিয়মীয়া আৰক্ষী নজৰদাৰী বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ঘটনাৰ সৈতে জড়িত দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে। আৰক্ষীয়ে ঘটনাটোৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে।

সম্পাদকীয়

ইথানল মিশ্রণ: বহনক্ষমতাও হওক অগ্রাধিকার

ভাৰতৰ শক্তি সুৰক্ষা শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে ইথানল মিশ্রণ কাৰ্যসূচীয়ে যোৱা দহ বছৰত এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য অৰ্জন কৰিছে। ২০১৪ চনত মাত্ৰ ১.৫ শতাংশ ইথানল মিশ্রণৰ পৰা দেশে সময়সীমাৰ আগতেই ২০ শতাংশ ২০ লক্ষ্যত উপনীত হৈছে। ইয়াৰ ফলত খাৰুৱা তেলৰ আমদানি হ্ৰাস, বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ সঞ্চয় আৰু কৃষকৰ আয় বৃদ্ধিৰ দৰে বহু ইতিবাচক ফল লাভ কৰা হৈছে। চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি, এই পদক্ষেপে বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ ব্যয় যথেষ্ট হ্ৰাস কৰাৰ লগতে লাখ লাখ কৃষকক অতিৰিক্ত উপাৰ্জনৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু এই সফলতাৰ আঁৰত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ

প্ৰশ্নও উত্থাপিত হৈছে। বৰ্তমান ভাৰতৰ অধিকাংশ ইথানল উৎপাদন আখ, মাকৈ আৰু ভঙা চাউলৰ দৰে প্ৰথম প্ৰজন্মৰ কৃষিজ কেঁচামালৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। বিশেষকৈ আখ হৈছে অধিক পানী ব্যৱহাৰ কৰা শস্য। যদি ইথানলৰ চাহিদা অব্যাহতভাৱে বৃদ্ধি পায়, তেন্তে ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ ওপৰত চাপ, মাটিৰ উৰ্বৰতা, শস্যৰ বৈচিত্ৰ্য আৰু খাদ্য সুৰক্ষাৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকা আছে।

ভাৰতৰ শক্তি নীতি এতিয়া কেৱল মিশ্রণৰ শতাংশ বৃদ্ধিত সীমাবদ্ধ থাকিব নালাগে। কৃষিজ অৱশিষ্ট, পৌৰ আৱৰ্জনা আৰু অখাদ্য জৈৱ পদাৰ্থৰ

পৰা দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ জৈৱ ইন্ধন উৎপাদনক অধিক গুৰুত্ব দিয়াটো সময়ৰ দাবী। ইয়াৰ ফলত কৃষিক্ষেত্ৰৰ আৱৰ্জনাৰ সদ্ব্যৱহাৰ হোৱাৰ লগতে বায়ু প্ৰদূষণো হ্ৰাস পাব।

দেশৰ শক্তি আত্মনিৰ্ভৰশীলতা নিশ্চিত কৰাটো নিঃসন্দেহে প্ৰয়োজনীয়। কিন্তু সেই লক্ষ্য অৰ্জনৰ পথো বহনক্ষম, পৰিৱেশ-অনুকূল আৰু কৃষক-স্বার্থ সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব। ইথানল কাৰ্যসূচীৰ প্ৰকৃত সফলতা কেৱল মিশ্রণৰ হাৰ বৃদ্ধি নহয়, বৰঞ্চ এনে এক শক্তি ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাত, যিয়ে একেলগে অৰ্থনীতি, কৃষি, পৰিৱেশ আৰু ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ স্বার্থক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব।

এটা দেশ, এটা নিৰ্বাচন: প্ৰশাসনিক ব্যয় হ্ৰাসৰ এক সম্ভাৱ্য পথ

জন জন বিচার
... প্রবীণ কৌশল

ভাৰতৰ নিৰ্বাচনক বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক অনুশীলন বুলি কোৱা হয়। কিন্তু এই বিশাল গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ আঁৰত লুকাই থাকে এক বৃহৎ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা-লাখ লাখ কৰ্মচাৰীৰ নিয়োগ, চৰকাৰী সেৱাৰ সাময়িক ব্যাঘাত আৰু বাৰে বাৰে হোৱা বিপুল ব্যয়।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অৰ্থনৈতিক উপদেষ্টা পৰিষদ (ইএসী-পীএম)-এ শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰা এখন 'এটা দেশ, এটা নিৰ্বাচন' শীৰ্ষক ৰকিং পেপাৰে এই বিতৰ্কত এক নতুন দিশ উন্মোচন কৰিছে। ৰাজনৈতিক যুক্তিৰ বাহিৰলৈ গৈ এই গৱেষণাপত্ৰই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশাসনিক লাভৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে।

গৱেষণাৰ মতে, যদি লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত হয়, তেন্তে পাঁচ বছৰৰ নিৰ্বাচনী চক্ৰত ভোটগ্ৰহণ কৰ্মচাৰীৰ নিয়োগ প্ৰায় ২৮ শতাংশ হ্ৰাস পাব, অৰ্থাৎ প্ৰায় ২৬ লাখ কৰ্মচাৰীৰ সমপৰিমাণ সঞ্চয় হ'ব। প্ৰশিক্ষণ আৰু নিয়োগৰ সময় হিচাপ কৰিলে ইয়াৰ ফলত ৰ.০৪ কোটি মানৰ-দিবস সঞ্চয় হ'ব পাৰে।

প্ৰথম দৃষ্টিত এই তথ্য কেৱল এটা প্ৰশাসনিক পৰিসংখ্যা যেন লাগিব পাৰে। কিন্তু গভীৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰিলে ইয়াৰ লগত শাসন ব্যৱস্থা, জনসেৱা আৰু প্ৰতিষ্ঠানগত দক্ষতাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে।

বৰ্তমান ভাৰতত লোকসভা আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন ভিন্ন সময়ত অনুষ্ঠিত হয়। ফলত প্ৰায় গোটেই বছৰটো কোনো নহয় কোনো ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে। প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ বাবে পীঠাসীন বিষয়া, ভোটগ্ৰহণ বিষয়া আৰু আন কৰ্মচাৰীসকলক পুনৰ পুনৰ নিয়োগ কৰিবলগীয়া হয়।

এই কৰ্মচাৰীসকলৰ উল্লেখযোগ্য অংশ

বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক। তদুপৰি বহু ভোটকেন্দ্ৰ বিদ্যালয় চৌহদত স্থাপন কৰা হয়। ফলস্বৰূপে পাঠদান ব্যাহত হয়, শৈক্ষিক কেলেণ্ডাৰ পিছ

দৰে কাৰণসমূহ বিবেচনা কৰাৰ পিছত সম্ভাৱ্য লাভ ৩০ শতাংশৰ পৰা ২৮ শতাংশলৈ সংশোধন কৰা হৈছে। এই

আচৰণবিধি জাৰি হয় আৰু বহু চৰকাৰী সিদ্ধান্ত আৰু উন্নয়নমূলক কাম সাময়িকভাৱে স্থগিত থাকে। সেয়েহে নিৰ্বাচনৰ সংখ্যা

কমিলে শাসন ব্যৱস্থাৰ গতি বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনাও নুই কৰিব নোৱাৰি।

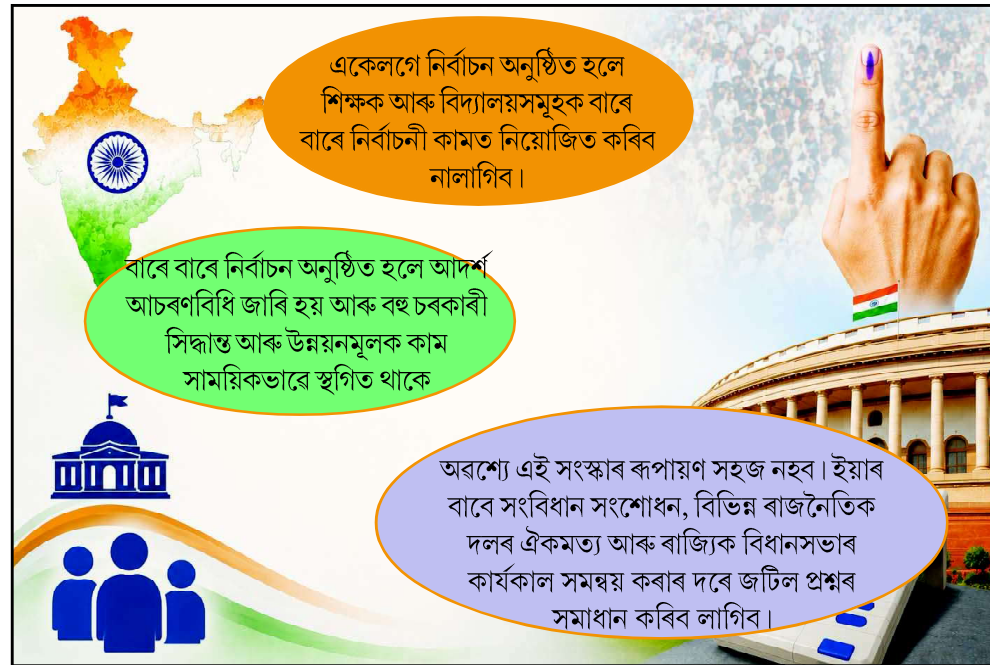
আৰ্থিক দিশৰ পৰাও একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিলে নিৰাপত্তা, লজিস্টিক ব্যৱস্থা আৰু প্ৰশাসনিক ব্যয় যথেষ্ট হ্ৰাস পাব পাৰে। যদিও ইয়াৰ সঠিক পৰিমাণ সময় আৰু পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল।

অৱশ্যে এই সংস্কাৰ ৰূপায়ণ সহজ নহ'ব। ইয়াৰ বাবে সংবিধান সংশোধন, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ একমত আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল সমন্বয় কৰাৰ দৰে জটিল প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰিব লাগিব। গৱেষণাপত্ৰখনে নিজেও স্বীকাৰ

কৰিছে যে আৰম্ভণিৰ পৰ্যায়ত সাময়িকভাৱে কৰ্মচাৰীৰ প্ৰয়োজন বৃদ্ধি পাব পাৰে।

তথাপিও, দীৰ্ঘম্যাদী লাভসমূহ বিবেচনা কৰিলে এই বিষয়ত যুক্তিসংগত আৰু তথ্যভিত্তিক আলোচনা অতি প্ৰয়োজনীয়। ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা শক্তিশালী যদিও সময়ৰ সৈতে প্ৰশাসনিক সংস্কাৰৰো প্ৰয়োজন আছে।

'এটা দেশ, এটা নিৰ্বাচন' সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে অধিকাংশ বিতৰ্ক ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা হৈছে। কিন্তু ইএসী-পীএম এই অধ্যয়নে আলোচনাটোক তথ্যভিত্তিক নীতি-নিৰ্ধাৰণৰ দিশলৈ লৈ গৈছে। মূল প্ৰশ্নটো এতিয়া এই নহয় যে একেলগে নিৰ্বাচন তাত্ত্বিকভাৱে ভাল নে বেয়া; বৰঞ্চ ৰাজনৈতিক, সাংবিধানিক আৰু প্ৰশাসনিক সকলো দিশৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ পথ কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি।



পৰে আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ পঢ়াশুনিৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰে।

গৱেষণা পত্ৰখনত এই দিশটোক বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে শিক্ষক আৰু বিদ্যালয়সমূহক বাৰে বাৰে নিৰ্বাচনী কামত নিয়োজিত কৰিব নালাগিব। শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে এইটো এক উল্লেখযোগ্য লাভ হ'ব পাৰে।

বৰ্তমান ব্যৱস্থাত পৃথক পৃথক নিৰ্বাচনৰ বাবে একেটা ভোটকেন্দ্ৰত বাৰে বাৰে পৃথক দল নিয়োগ কৰিবলগীয়া হয়। উদাহৰণস্বৰূপে, লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ পৃথক নিৰ্বাচনত একেটা কেন্দ্ৰত মুঠ নজন কৰ্মচাৰী লাগিব পাৰে। কিন্তু একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে একেটা দলৰ ছয়জন কৰ্মচাৰীয়েই দুয়োটা ভোটদান সম্পন্ন কৰিব পাৰিব।

গৱেষণাপত্ৰখনে ইতিহাসভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ কৰি দেখুৱাইছে যে কিছুমান ৰাজ্যত বিধানসভা আগতীয়াকৈ ভংগ হোৱা বা ইতিমধ্যে সমকালীন নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ

পদ্ধতিগত সতৰ্কতাই গৱেষণাটোৰ বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি কৰিছে।

অৱশ্যে গৱেষণাখনে নিজৰ সীমাবদ্ধতাও স্বীকাৰ কৰিছে। ইয়াত কেৱল ভোটগ্ৰহণ কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা লাভৰ মূল্যায়ন কৰা হৈছে। নিৰাপত্তা বাহিনী, ইভিএম পৰিচালনা বা ভোটগণনাৰ সৈতে জড়িত কৰ্মচাৰীসকলক এই অধ্যয়নত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই।

'এটা দেশ, এটা নিৰ্বাচন'ক লৈ হোৱা বৃহত্তৰ বিতৰ্ক কেৱল প্ৰশাসনিক দক্ষতাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয়। সমালোচকসকলে যুক্তি দিয়ে যে ইয়াৰ ফলত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা, আঞ্চলিক ৰাজনীতি আৰু গণতান্ত্ৰিক জবাবদিহিতাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। এই উদ্বেগসমূহো সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু গভীৰভাৱে বিবেচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে।

কিন্তু একে সময়তে এইটোও সত্য যে বাৰে বাৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে আদৰ্শ

২,০০০ বছৰৰ পিছত পুনৰ জাগি উঠিল 'সোণৰ পাহাৰ'

জন জন বিচাৰ

...শ্ৰেণী বিশেষ ডেস্ক

ভাৰতত সোণৰ চাহিদা প্ৰতিবছৰে বৃদ্ধি পাইছে। কিন্তু সেই তুলনাত দেশীয় উৎপাদন অতি কম। এনে সময়তে আন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ কুৰ্ণুল জিলাৰ ঐতিহাসিক স্বৰ্ণগিৰি পূৰ্বৰ জোন্নাগিৰি অঞ্চলত দেশৰ প্ৰথমখন ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্ৰাথমিক সোণৰ খনিত বাণিজ্যিক উৎপাদন আৰম্ভ হোৱাটো ভাৰতৰ খনন উদ্যোগৰ বাবে এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত হিচাপে বিবেচিত হৈছে।

মুখ্যমন্ত্ৰী এন. চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে এই প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ লগতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি ইয়াক ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ এক নতুন অধ্যায় বুলি অভিহিত কৰে।

কিয় বিশেষ এই খনি ?

স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যক্তিগত খণ্ডই বৃহৎ পৰিসৰত সোণৰ প্ৰাথমিক খনন আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰায় ৪০৫ কোটি টকাৰ বিনিয়োগেৰে গঢ়ি উঠা এই প্ৰকল্পত আধুনিক প্ৰযুক্তি, খনিজ



প্ৰক্ৰিয়াকৰণ ব্যৱস্থা আৰু উন্নত আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তোলা হৈছে।

প্ৰকল্পটোৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰায় ৬০০ একৰ ভূমিত উৎপাদন আৰম্ভ হৈছে। খনিটোৰ বাবে পানী যোগান নিশ্চিত কৰিবলৈ ১৮ কিলোমিটাৰ দীঘল পাইপলাইনো স্থাপন কৰা হৈছে।

আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰতা কমাব পাৰিবনে ?

বৰ্তমান ভাৰতত বছৰি প্ৰায় ১.৫ টন সোণ উৎপাদন হয়, যিটো দেশৰ মুঠ চাহিদাৰ অতি সৰু অংশ। অধিকাংশ সোণ বিদেশৰ পৰা আমদানি কৰিবলগীয়া হয়, যাৰ ফলত বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ ওপৰত যথেষ্ট চাপ

পৰে।

স্বৰ্ণগিৰি খনিৰে প্ৰথম বছৰতে প্ৰায় ৪০০ কিলোগ্ৰাম সোণ উৎপাদনৰ লক্ষ্য লৈছে। পিছৰ কেইবছৰত এই উৎপাদন ধাপে ধাপে চটনলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। লক্ষ্য পূৰণ হলে দেশীয় উৎপাদনত এই খনিৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াব।

চাকৰি আৰু আঞ্চলিক উন্নয়নৰ নতুন সম্ভাৱনা

এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰায় ৭০০ জন লোকৰ নিয়োগৰ সুযোগ সৃষ্টি হ'ব। চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি, এই

কৰ্মচাৰীৰ প্ৰায় ৮০ শতাংশ স্থানীয় অঞ্চলৰ পৰা নিয়োগ কৰাৰ লক্ষ্য ৰখা হৈছে।

ইয়াৰ উপৰিও, খনিৰ কাষতে আধুনিক গল্ড জুৱেলাৰী মেনুফেক্চাৰিং পাৰ্ক স্থাপনৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। ইয়াৰ ফলত গহনা নিৰ্মাণ, ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ, দক্ষতা বিকাশ আৰু স্থানীয় ব্যৱসায়ৰ নতুন দুৱাৰ মুকলি হ'ব।

ইতিহাসৰ সৈতে জড়িত এক ভূখণ্ড

এই অঞ্চলৰ ইতিহাস প্ৰায় ২,০০০ বছৰৰো অধিক পুৰণি। ইতিহাসবিদসকলৰ মতে, মউৰ্য সম্ৰাট অশোকৰ সময়তো ইয়াত সোণ আহৰণ কৰা হৈছিল। ওচৰৰ এৰাণ্ডি অঞ্চলত উদ্ধাৰ হোৱা মউৰ্য যুগৰ শিলালিপিসমূহে এই অঞ্চলৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্বৰ প্ৰমাণ বহন কৰে।

এই ঐতিহ্যৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে জোন্নাগিৰিৰ নাম আনুষ্ঠানিকভাৱে 'স্বৰ্ণগিৰি'লৈ সলনি কৰিছে।

নতুন শৃংখৰৰ সম্ভাৱনা ?

ভূতত্ত্ববিদসকলৰ মতে, কুৰ্ণুল আৰু ৰায়লসীমা অঞ্চলত বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণৰ ভঁৰাল থকাৰ

সম্ভাৱনা আছে। স্বৰ্ণগিৰিৰ সফলতাৰ পিছত আন বহু স্থানতো অনুসন্ধান তীব্ৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। এই কাৰণেই বহুতে ইয়াক ভাৰতৰ 'নতুন' হিচাপে অভিহিত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে।

উন্নয়নৰ সৈতে পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্যও জৰুৰী

খনন উদ্যোগে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন, ৰাজহ বৃদ্ধি আৰু কৰ্মসংস্থানৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিলেও পৰিৱেশ সুৰক্ষা, পানী ব্যৱস্থাপনা, বনাঞ্চল সংৰক্ষণ আৰু স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ নিশ্চিত কৰাটোও সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ। বহনক্ষম উন্নয়নৰ নীতি মানি আগবাঢ়িলেহে এনে বৃহৎ প্ৰকল্প দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে সফল হ'ব।

স্বৰ্ণগিৰি খনিৰে ভাৰতৰ খনিজ অৰ্থনীতিত এক নতুন আশা কঢ়িয়াই আনিছে। যদি এই প্ৰকল্প সফলতা, আধুনিক প্ৰযুক্তি, পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু স্থানীয় জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণৰ সৈতে আগবাঢ়ে, তেন্তে ই কেৱল আন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰেই নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হ'ব।

মহা বিকাশ আঘাডীৰ ভিতৰত ফাট ?

জন জন বিচাৰ

...আইজল

মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতি আকৌ এবাৰ উত্তপ্ত। বিধানসভাৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত মহা বিকাশ আঘাডী (এমবীএ) কৌশলগত বৈঠকত ৬০ জন বিধায়কৰ ভিতৰত ২৩ জনৰ অনুপস্থিতিয়ে বিৰোধী শিবিৰত নতুন বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছে। বৈঠকত উদ্ধাৰ ঠাকৰেৰ এক প্ৰশ্নে ৰাজনৈতিক মহলত বিশেষ চৰ্চাৰ সৃষ্টি কৰিছে- আমি সঁচাকৈয়ে একেলগে আছোনে ?

এই প্ৰশ্ন কেৱল ক্ষণিকৰ আবেগ নে বিৰোধী ঐক্যৰ ভিতৰত গভীৰ সংকটৰ ইংগিত-এই বিষয়েই এতিয়া ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকৰ মূল আলোচনা।

অনুপস্থিতিৰ ৰাজনীতি

যিকোনো বৃহৎ ৰাজনৈতিক মিত্ৰজোঁটত মতভেদ স্বাভাৱিক। কিন্তু কৌশলগত বৈঠকত বৃহৎ সংখ্যক বিধায়কৰ অনুপস্থিতি মাত্ৰ সাংগঠনিক দুৰ্বলতা বুলি উলাই দিব নোৱাৰি। বিশেষকৈ যেতিয়া কেইদিনমান আগতেই উদ্ধাৰ ঠাকৰেৰ দলৰ কেইবাজনো সাংসদে একনাথ শিন্দে শিবিৰত যোগদান কৰিছে,



তেতিয়া এই ঘটনাই অধিক তাৎপৰ্য লাভ কৰিছে।

মিত্ৰজোঁটৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান-বিশ্বাস

মহা বিকাশ আঘাডী হৈছে ভিন্ন ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰ তিনিটা মুখ্য শক্তিৰ মিত্ৰজোঁট। চৰকাৰত থাকোঁতে ক্ষমতাৰ লক্ষ্যই একতা বজাই ৰাখিছিল। কিন্তু বিৰোধীতাত সেই একতাক অটুট ৰাখিবলৈ কেৱল বিজেপি-বিৰোধিতা যথেষ্ট নহয়। সুস্পষ্ট নেতৃত্ব, একে ৰাজনৈতিক বাৰ্তা আৰু মাটিৰ স্তৰত সমন্বয়ৰো প্ৰয়োজন।

উদ্ধাৰ ঠাকৰেৰ বক্তব্যৰ পৰা বুজা যায় যে তেওঁ মিত্ৰদলসমূহৰ মাজত অধিক সক্ৰিয় সহযোগিতা আশা কৰিছে।

মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিত

নতুন সমীকৰণ

২০২২ চনত শিৱসেনাৰ বিভাজন আৰু তাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰবাদী কংগ্ৰেছ দল-ৰ ভাঙোনে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিক সম্পূৰ্ণ নতুন ৰূপ দিছে। দলত্যাগ, পুনৰ সংগঠন আৰু নেতৃত্বৰ প্ৰতিযোগিতাই এতিয়া ৰাজ্যখনৰ ৰাজনীতিৰ মূল বৈশিষ্ট্য হৈ পৰিছে।

এই পৰিস্থিতিত এমবীএ-ৰ সন্মুখত দুটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান-নিজৰ সংগঠন শক্তিশালী কৰা। -জনসাধাৰণৰ মাজত এক বিকল্প শাসনৰ বিশ্বাসযোগ্য ছবি গঢ়ি তোলা।

শাসক আৰু বিৰোধী-দুয়োৰে পৰীক্ষা

গণতন্ত্ৰত শক্তিশালী বিৰোধী দলৰ উপস্থিতি অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। বিৰোধী শিবিৰ যদি নিজৰ ভিতৰতে বিভক্ত হয়, তেন্তে চৰকাৰক জবাবদিহি কৰোৱাটো কঠিন হৈ পৰে। আনহাতে, শাসক দলৰ বাবেও ই এক ৰাজনৈতিক সুবিধা সৃষ্টি কৰে।

সেয়েহে এই সংকট কেৱল এমবীএ-ৰ নহয়; ই গণতান্ত্ৰিক ৰাজনীতিৰো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা।

আগলৈ কি ? : উদ্ধাৰ ঠাকৰেৰ এই আত্মসমালোচনামূলক মন্তব্যই হয়তো মিত্ৰজোঁটৰ ভিতৰত নতুন আলোচনা আৰম্ভ কৰিব। যদি নেতৃত্ব মতভেদ দূৰ কৰি সংগঠনক পুনৰ শক্তিশালী কৰিব পাৰে, তেন্তে এমবীএ পুনৰ শক্তিশালী বিৰোধী শক্তি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব পাৰে। অন্যথা, এই অনৈক্যই আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিৰোধী শিবিৰক অধিক দুৰ্বল কৰিব পাৰে।

গণতন্ত্ৰত ৰাজনৈতিক মিত্ৰজোঁট গঠন কৰাতকৈ তাক টিকাই ৰখাটো অধিক কঠিন। আদৰ্শ, নেতৃত্ব, আস্থা আৰু জনস্বার্থ-এই চাৰিটা স্তম্ভ মজবুত থাকিলেহে যিকোনো মিত্ৰজোঁট দীৰ্ঘস্থায়ী হয়।

বান্ধৱা শ্ৰমিক নিৰ্যাতন

মুজাফফৰনগৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ

মুজাফফৰনগৰ জিলাৰ এখন কাগজৰ প্লেট নিৰ্মাণ কাৰখানাত বান্ধৱা শ্ৰমিক হিচাপে আবদ্ধ কৰি ৰখা ১২ জন শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰাৰ তদন্তত এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। আৰক্ষীৰ অভিযোগ অনুসৰি, কাৰখানাখনত অমানৱীয় নিৰ্যাতনৰ ফলত অৰ্জুন নামৰ এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু পিছত তেওঁৰ মৃতদেহ এটা বেগত ভৰাই পেলাই দিয়া হৈছিল। এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত কাৰখানাৰ মালিক অংকিত বালিয়ান আৰু শিৱা ত্যাগীৰ বিৰুদ্ধে নতুন গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। শিৱা ত্যাগীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যদিও মূল অভিযুক্ত অংকিত বালিয়ান পলাতক। তেওঁৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে দুটা বিশেষ দল গঠন কৰিছে। উদ্ধাৰ হোৱা শ্ৰমিকসকলে অভিযোগ কৰে যে তেওঁলোকক মাহিলী দৰমহাৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আনি এবছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি কাৰখানাত আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিল। পলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে তেওঁলোকক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ, গৰম লোহাৰে দণ্ড কৰা, কোৰাৰে কোবোৱা আৰু কুকুৰেৰে আক্ৰমণ কৰোৱা হৈছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে।

ধৰ্মনৰে পুনৰ ৰূপালী পৰ্দাত ৰজনীকান্ত

দক্ষিণ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰৰ থালাইভা তথা ভাৰতীয় চিনেমাৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় তাৰকা ৰজনীকান্তৰ নতুন ছবিৰ নাম আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছে- ধৰ্মন। ছবিখনৰ নাম ঘোষণাৰ লগে লগেই সামাজিক মাধ্যমত অনুৰাগীসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহৰ সৃষ্টি হৈছে।

এতিয়ালৈকে থালাইভাৰ ১৭৩ নামেৰে পৰিচিত এই ছবিখন পৰিচালনা কৰিব সফল পৰিচালক অশ্বথ মাৰিমুথুৰে, যিয়ে 'ড্ৰেগন' ছবিৰ জৰিয়তে বিশেষ খ্যাতি অৰ্জন কৰিছিল। ছবিখন প্ৰযোজনা কৰিছে অভিনেতা তথা প্ৰযোজক কমল হাসানৰ প্ৰতিষ্ঠান ৰাজ কমল ফিল্মছ ইণ্টাৰনেশ্যনেলে।

পোষ্টাৰে কি কলে?

মুকলি কৰা শীৰ্ষক পোষ্টাৰত ৰজনীকান্তক এখন চিকিৎসালয়ৰ অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত হাতত অস্ত্ৰোপচাৰৰ ছুৰী লৈ দেখা গৈছে। দৃশ্যটোৱে ইংগিত দিয়ে যে ছবিখনত তেওঁ এজন চিকিৎসকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব পাৰে। একে সময়তে

পোষ্টাৰৰ নাটকীয় উপস্থাপনে ছবিখনৰ কাহিনীত ন্যায়-অন্যায়ৰ সংঘাত আৰু শক্তিশালী এক সামাজিক বাৰ্তা থকাৰ সম্ভাৱনাও উজ্জ্বল কৰিছে।

ধৰ্মন -নামটোৱেই কিয় তাৎপৰ্যপূৰ্ণ?

'ধৰ্মন' নামটোৱে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ এক গভীৰ মূল্যবোধক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। 'ধৰ্ম' কেৱল ধৰ্মীয় অৰ্থত নহয়, ন্যায়, কৰ্তব্য, সততা আৰু নৈতিকতাৰ প্ৰতীক হিচাপেও ব্যৱহৃত হয়। কমল হাসানে শীৰ্ষক ঘোষণা কৰাৰ সময়ত লিখা 'ধৰ্মমে ভেঙ্কু ধৰ্মই শেষত জয়ী হয়' বাক্যই ছবিখনৰ মূল ভাবধাৰাৰ আভাস দিয়ে।

দুজন কিংবদন্তীৰ একত্ৰ

ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ দুজন কিংবদন্তী-ৰজনীকান্ত আৰু কমল হাসান-একে প্ৰকল্পত একেলগে থকাটো অনুৰাগীসকলৰ বাবে বিশেষ আকৰ্ষণৰ বিষয়। যদিও কমল হাসানে ছবিখনত অভিনয় কৰা নাই, তেওঁৰ প্ৰযোজনা সংস্থা ই এই বৃহৎ প্ৰকল্পৰ দায়িত্ব লোৱাত



ছবিখনৰ প্ৰতি কৌতূহল বহুগুণে বৃদ্ধি পাইছে।

শক্তিশালী প্ৰযুক্তিগত দল

ছবিখনৰ সংগীত পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছে অনিৰুদ্ধ ৰবিচন্দৰ, যাৰ সংগীতে সাম্প্ৰতিক বহু ব্লকবাস্টাৰ ছবিক সফলতা প্ৰদান কৰিছে। চিত্ৰগ্ৰহণ কৰিব নিকেথ বোশ্মি, সম্পাদনা কৰিব প্ৰদীপ ই. ৰাঘৱে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপ্ত যুটি অম্বাৰিভে একচন দৃশ্যৰ দায়িত্ব লব্ধ।

দক্ষিণ ভাৰতীয় চিনেমাৰ বিশ্বব্যাপী প্ৰভাৱ

শেহতীয়া বছৰবোৰত দক্ষিণ ভাৰতীয় ছবিয়ে কেৱল ভাৰততেই নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বতে এক বিশেষ পৰিচয় গঢ়ি তুলিছে। 'বাহুবলী', 'কেজিএফ', 'পুষ্পা', আৰু আৰ আৰ আদিৰ সফলতাৰ পিছত প্ৰতিটো বৃহৎ দক্ষিণ ভাৰতীয় ছবিৰ ওপৰত দৰ্শকৰ প্ৰত্যাশা বৃদ্ধি পাইছে। ঋতুধৰ্মনস্কৃৎ সেই ধাৰাবাহিকতাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোজন হ'ব বুলি চলচ্চিত্ৰ মহলে আশা প্ৰকাশ কৰিছে।

পুণেৰ ব্যৱসায়ী কেতন অৱপালৰ হত্যাকাণ্ডে পুনৰ এবাৰ সমগ্ৰ দেশক নাড়া দি গম্বল। অভিযোগ অনুসৰি, তেওঁৰ পত্নী আৰু তেওঁৰ প্ৰেমিকেই পৰিকল্পিতভাৱে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰে। ইয়াৰ আগতেও ৰাজা ৰঘুবংশী, দুশ্ৰদ্ধা ৰালকৰ, মুস্কান-সাহিল আদি বহু ঘটনাই একেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে- সম্পৰ্ক শেষ কৰিব বিচাৰিলে কিয় কিছুমানে হত্যা কৰাৰ দৰে জঘন্য পথ বাছি লয়?

এইবোৰ কেৱল অপৰাধৰ ঘটনা নহয়; ই আমাৰ সমাজ, পৰিয়াল, মানসিক স্বাস্থ্য আৰু মূল্যবোধৰ ওপৰত গভীৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে।

প্ৰেমৰ পৰা প্ৰতিশোধলৈ

প্ৰেম বা বিবাহিত সম্পৰ্কত মতানৈক্য, বিশ্বাসঘাতকতা বা নতুন সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠা নতুন কথা নহয়। কিন্তু আগতে যত্নত বিচ্ছেদ, আইনী পথ বা সামাজিক সমাধান বিচৰা হৈছিল, আজিৰ কিছুমান ঘটনাত সেই ঠাইত হত্যা, যড়যন্ত্ৰ আৰু হিংসাই স্থান দখল কৰিছে।

মনোবিজ্ঞানীসকলৰ মতে, যেতিয়া মানুহে নিজৰ ইচ্ছা, অহংকাৰ বা স্বার্থক সকলোতকৈ ডাঙৰ বুলি ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া আনজন মানুহৰ জীৱনৰ মূল্য তেওঁলোকৰ



সামাজিক ভাৱে পৃথক হোৱাটো অধিক যুক্তিসংগত। কিন্তু হত্যা কোনো সমস্যাৰ সমাধান হ'ব নোৱাৰে; ই কেৱল আনবহু জীৱন ধ্বংস কৰে।

সমাজৰ বাবে সতৰ্কবাণী :

এনে ঘটনাই সমাজত বিশ্বাসৰ সংকট সৃষ্টি কৰিছে। স্বামী-স্ত্ৰী, প্ৰেমিক-প্ৰেমিকা বা পৰিয়ালৰ মাজত সন্দেহবৃদ্ধি পাইছে। সেয়েহে বিদ্যালয়, পৰিয়াল আৰু সমাজে আৱেগিক শিক্ষা, মানসিক স্বাস্থ্যৰ যত্ন আৰু সুস্থ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ শিক্ষা অধিক গুৰুত্ব দিব লাগিব।

কোনো সম্পৰ্কৰ অন্ত হ'ব পাৰে, কিন্তু মানুহৰ জীৱনৰ মূল্য কেতিয়াও শেষ নহয়। মতভেদ হলে কথা পাতক, পৰামৰ্শ লওক, আইনৰ সহায় লওক-কিন্তু হিংসা কেতিয়াও সমাধান নহয়। এখন সুস্থ সমাজ গঢ়িবলৈ সহনশীলতা, পাৰস্পৰিক সন্মান আৰু মানসিক সুস্থতাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াটো সময়ৰ দাবী।

ওচৰত কমি যায়। সেই সময়তেই বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায়।

কিয় বৃদ্ধি পাইছে এনে ঘটনা?

বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, কেইবাটাও কাৰণ একেলগে কাম কৰে-

মানুহে কি কবৰ ভয় : সমাজৰ সমালোচনাৰ ভয়ত বহুতে সম্পৰ্ক শেষ কৰাৰ সাহস নাপায়।

পৰিয়ালৰ চাপ : বিশেষকৈ বিবাহিত জীৱনত পৰিয়ালৰ সন্মানৰ কথা ভাৱি সত্য লুকুৱাই ৰখা হয়।

আৱেগ নিয়ন্ত্ৰণৰ অভাৱ : খং, ঈৰ্ষা আৰু প্ৰতিশোধৰ অনুভূতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলে অপৰাধৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে।

অৰ্থনৈতিক নিৰ্ভৰশীলতা : বিচ্ছেদৰ পিছত জীৱন কেনেকৈ চলিব, সেই চিন্তাও বহু ক্ষেত্ৰত কাৰণ হয়।

মানসিক স্বাস্থ্যৰ অৱনতি : উদ্বেগ, হতাশা, আত্মকেন্দ্ৰিকতা বা ব্যক্তিত্বজনিত সমস্যাই সিদ্ধান্ত লোৱাত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে।

চলচ্চিত্ৰ আৰু ছফ্টৱেল মিডিয়াৰ প্ৰভাৱ : আজিৰ

ডিজিটেল যুগত বহু চলচ্চিত্ৰ, ৱেব ছিৰিজ আৰু সামাজিক মাধ্যমত অপৰাধীক কেতিয়াবা চতুৰ বা হিৰোৰ দৰে উপস্থাপন কৰা হয়। যদিও অধিকাংশ দৰ্শকে ইয়াক কেৱল বিনোদন হিচাপে লয়, তথাপি মানসিকভাৱে অস্থিৰ কিছুমান ব্যক্তিৰ ওপৰত ইয়াৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে।

সম্পৰ্ক শেষ কৰাটো অপৰাধ নহয় : সুস্থ সমাজত কোনো সম্পৰ্ক জেৰকৈ টিকাই ৰখাৰ প্ৰয়োজন নাই। যদি দুয়োপক্ষৰ মাজত বিশ্বাস, সন্মান বা ভালপোৱা নাথাকে, তেন্তে আইনী আৰু

"A nation grows stronger not when it avoids challenges, but when it faces them with truth, courage, and accountability."

Between Delhi and Aizawl

Why Mizoram's ZPM Is Choosing Cooperation Over Coalition

Jan Jan Vichar
...Aizawl

In an era when political alliances often determine the direction of governance, Mizoram's ruling Zoram People's Movement (ZPM) has chosen a different path. Chief Minister Lalduhoma recently disclosed that both Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah have repeatedly invited the party to join the National Democratic Alliance (NDA). Yet, the ZPM has politely declined, preferring a relationship of cooperation without formal political alignment.

The announcement is significant not because it signals confrontation with the Centre, but because it reflects a distinctive political philosophy rooted in regional autonomy.

Addressing a press conference in Aizawl, Lalduhoma made it clear that joining the NDA is 'not under consideration' and has never been discussed by the party's Political Affairs Committee. Instead, the ZPM believes that maintaining cordial relations with the Union Government while preserving its independent regional identity best serves the interests of Mizoram.

A Regional Party with a National Outlook

The ZPM describes itself as 'a regional party with a national outlook.' This approach reflects Mizoram's unique political history. Long before statehood, regional parties often worked constructively with whichever party ruled in New Delhi, ensuring that the state's developmental needs were addressed without necessarily becoming part of the ruling coalition.



ZPM Rejects NDA Membership: Mizoram Chief Minister Lalduhoma clarified that the Zoram People's Movement (ZPM) has not joined the NDA, and the issue is not under consideration.

PM Modi & Amit Shah Invited ZPM:

Lalduhoma revealed that Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah have repeatedly invited the party to join the NDA since it formed the government.

Cooperation Without Coalition: The ZPM prefers to maintain cordial relations with the Centre while preserving its independent regional identity, rather than becoming a formal NDA ally.

According to Lalduhoma, this tradition helped Mizoram secure infrastructure, development projects, and administrative support while allowing regional leaders to retain their independent political voice.

Unlike many regional parties that have either aligned with or opposed the Centre on ideological grounds, the ZPM seeks a middle path—supporting development initiatives while retaining complete political autonomy.

Pragmatism Over Politics

The recent alliance between the ZPM and the BJP in the Chakma Autonomous District Council (CADC) created speculation that the party was preparing to join the NDA. Lalduhoma, however, dismissed such assumptions.

He explained that the CADC arrangement was purely a matter of political arithmetic. No single party had enough members to form the Executive Committee, making cooperation unavoidable. The alliance, he said, should not be interpreted as an ideological shift or a precursor to joining the NDA.

This distinction highlights an important feature of Indian federal politics: parties may cooperate on governance at one level while maintaining different political positions at another.

The Politics of Balance

For the BJP-led NDA, bringing influential regional parties into its fold remains an important political objective, particularly in the Northeast where regional aspirations play a significant role in electoral politics. An

alliance with the ZPM would further strengthen the NDA's presence in a strategically important border state.

For the ZPM, however, political independence appears equally valuable. Remaining outside formal alliances allows the party to negotiate directly with the Centre on issues concerning Mizoram while avoiding the perception that regional priorities are subordinate to national political agendas.

This balancing act also reflects the maturity of India's federal structure, where cooperation between the Centre and states need not always depend on coalition politics.

What Lies Ahead?

Although Lalduhoma has ruled out joining the NDA 'for now,' politics is rarely static. Electoral dynamics, national developments, and regional priorities can reshape political equations over time.

For the moment, however, the message from Aizawl is clear: the ZPM seeks partnership without political merger. It is willing to work closely with the Union Government on development and governance but is equally determined to preserve its independent regional identity.

In a political environment often divided into rigid camps, Mizoram's approach offers an alternative model—one that prioritises constructive engagement over formal alliance. Whether this strategy continues to benefit the state in the years ahead will depend not only on political calculations but also on how effectively cooperation translates into development for the people of Mizoram.

CBI Launches Nationwide Crack-down on Digital Arrest Scam

New Delhi : In one of its biggest coordinated operations against cybercrime, the Central Bureau of Investigation (CBI) on 24th June carried out raids at more than 80 locations across 16 states as part of its ongoing probe into the growing digital arrest scam. The nationwide operation, conducted under Operation Chakra, aims to dismantle organised cybercrime networks involved in defrauding victims through fake law enforcement and judicial threats.

The CBI constituted 60 special teams to conduct simultaneous searches in Punjab, Gujarat, Delhi, Maharashtra, Haryana, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Assam, West Bengal, Manipur, Karnataka and Odisha. According to the agency, the investigation covers over 200 cases linked to digital arrest frauds. During the operation, two suspects were arrested for allegedly creating shell companies and opening fraudulent bank accounts used to launder money obtained through cyber scams.

Investigators also uncovered evidence that the fraudsters had created a fake website closely resembling the official website of the Supreme Court of India. The website was allegedly used to deceive victims into believing they were under investigation by law enforcement agencies and to extort money. The case was registered after a complaint from the Supreme Court Registry.

The CBI said its investigation has revealed that the scam targeted both Indian and foreign nationals, highlighting the international dimensions of the cybercrime network.

FIFA World Cup 2026 Reaches Defining Stage as Giants March Ahead

— Jan Jan Vichar

... Pijush Saloi

The FIFA World Cup 2026 has entered a crucial phase, captivating football fans across the globe with a blend of thrilling encounters, surprise results, and historic achievements. Being hosted jointly by the United States, Canada, and Mexico, the tournament has already earned a place in football history as the first-ever World Cup featuring 48 participating nations, making it the largest edition since the competition began in 1930. However, the expanded format has also created opportunities for emerging football nations to challenge the established order, adding a fresh dimension to the world's most prestigious sporting event.

Among the teams that have already booked their places in the Round of 32 are Argentina, Germany, France, Norway, Mexico, and the United States. These sides have delivered strong performances during the group stage and are among the leading contenders for the title.

Defending champions Argentina continue to impress, led by veteran superstar Lionel Messi, who recently became the all-time leading goalscorer in FIFA World Cup history. France, spearheaded by Kylian Mbappé, and Ger-



Mexico goalkeeper Guillermo Ochoa (13) is celebrated by his team after the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City.

many have also demonstrated their championship credentials with convincing displays.

Teams such as Uzbekistan, Jordan, Curaçao, and Cape Verde have brought fresh excitement and demonstrated the growing global reach of football. Their participation reflects FIFA's goal of expanding opportunities through the 48-team format.

As the competition moves closer to the knockout stage, excitement continues to build across the host nations. Packed stadiums, passionate

supporters, and high-quality football have combined to make FIFA World Cup 2026 one of the most memorable editions of the tournament.

The World Cup has also produced several memorable moments and dramatic contests. Last-minute goals, stunning upsets, and remarkable individual performances have kept fans on the edge of their seats. Several matches have showcased the unpredictability that makes football the world's most popular sport.

Off the field, organisers have faced certain challenges. Weather conditions in some host cities have occasionally disrupted schedules, while concerns regarding playing surfaces at a few venues have sparked debate among players and coaches.

Technology has also played a major role in shaping the tournament experience. Advanced officiating systems, real-time analytics, and unprecedented digital coverage have brought fans closer to the action than ever before. Millions are following matches through multiple platforms, engaging in discussions across social media, and

consuming football content around the clock. In many ways, the World Cup is no longer confined to stadiums; it exists simultaneously on screens, smartphones, and online communities worldwide.

For Indian football fans, the tournament has provided an opportunity to witness the highest standards of international football while also drawing attention to the progress being made by emerging football nations. Many experts believe that the success of smaller countries in this World Cup offers valuable lessons for developing football systems around the world, including in India.

FIFA World Cup 2026 is shaping up to be one of the most memorable editions in the competition's rich history. The coming weeks promise intense drama, unforgettable moments, and perhaps a few more surprises before a new world champion is crowned. In that sense, the true legacy of FIFA World Cup 2026 may not be remembered solely through its champion, but through the way it redefined what a World Cup can be in the twenty-first century.



Switzerland's Remo Freuler (8) plays the ball in front of Canada's Stephen Eustaquio (7) during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia.

Venezuela Roacked by **Twin Earthquakes**

Powerful 7.2 & 7.5 Magnitude Quakes Trigger Massive Destruction, State of Emergency Declared as Rescue Race Intensifies, fatalities could range between 10,000 and 100,000

Jan Jan Vichar
...✍️Caracas

Venezuela is battling one of the worst natural disasters in its recent history after two powerful earthquakes measuring 7.2 and 7.5 on the Richter scale struck within less than a minute of each other on 24th June evening, causing widespread devastation across the country. The twin quakes flattened buildings, damaged vital infrastructure, and trapped hundreds beneath collapsed structures, prompting the government to declare a nationwide State of Emergency.

According to the U.S. Geological Survey (USGS), the first earthquake struck about 160 kilometres west of Caracas, followed just 39 seconds later by an even stronger tremor. Both earthquakes occurred at relatively shallow depths, making their impact significantly more destructive. More than twenty aftershocks were also re-



corded, forcing frightened residents to remain outdoors as fears of further collapses spread across affected cities.

The capital city, Caracas, bore the brunt of the disaster. Residential apartments, commercial buildings, offices, and public infrastructure suffered extensive damage. Roads cracked, power and communication networks were disrupted, and several districts reported collapsed buildings with people trapped beneath the debris. Rescue workers, firefighters, military person-

nel, and volunteers continued search-and-rescue operations through the night using heavy equipment and sniffer dogs in the hope of finding survivors.

Although Venezuelan authorities have not yet released an official nationwide death toll, the USGS issued a Red Alert, warning that the disaster could result in very high casualties because of the intensity of the earthquakes and the vulnerability of buildings in the affected region. Its preliminary modelling estimates that fatalities could range between 10,000 and

100,000, but these figures are projections rather than confirmed counts.

Interim President Delcy Rodríguez announced a nationwide state of emergency and appealed for international assistance. Expressing condolences to families who lost loved ones, she assured citizens that every available national resource had been mobilised for rescue and relief operations. Authorities also ordered people to stay away from damaged structures as powerful aftershocks continued to shake the country.

The disaster struck on Venezuela's Independence Day holiday, when most people were at home with their families, increasing the potential human toll. Witnesses described scenes of panic as buildings swayed violently and frightened residents rushed into the streets. Hospitals declared emergency protocols, while medical teams worked around the clock to treat the injured. The country's largest international airport, Simón Bolívar International Airport, was closed after suffering structural damage, disrupting domestic and international flights.

The international community responded swiftly. India expressed deep condolences, with Prime Minister Narendra Modi stating that India stands ready to provide every possible assistance to the people of Venezuela. The United States also announced its willingness to support rescue and humanitarian operations as emergency teams continue to assess the full scale of the catastrophe.

2020 Audit Report Flagged Ram Temple Management Lapses

Jan Jan Vichar
...✍️Lucknow

Fresh questions have emerged over the financial management of the Ram Temple Trust after reports indicated that an internal audit conducted in 2020 had identified serious shortcomings in donation management, record keeping, and administrative procedures—years before the alleged theft of temple offerings came to light.

According to reports, the audit, carried out shortly after the formation of the Trust, warned that the absence of a Standard Operating Procedure (SOP) for financial and administrative activities could undermine

SIT May Examine Earlier Audit as Probe into Alleged Offering Theft Continues

transparency and accountability. The auditors reportedly recommended comprehensive procedures for handling donations, maintaining records, managing human resources, and ensuring proper financial oversight.

The report is said to have expressed particular concern over the management of cash donations and jewellery offerings, recommending the maintenance of detailed stock registers, stronger monitoring systems, and trained personnel to supervise financial



transactions. It also highlighted deficiencies in data security, digital record management, and internal IT controls.

The developments come as a Special Investigation Team (SIT) examines allegations of theft and financial irregularities re-

lated to temple offerings. According to media reports, the SIT's preliminary findings have also raised questions about financial management within the Trust. Investigators are expected to examine whether the recommendations made in the 2020 audit were implemented or ignored.

The central issue now is whether the deficiencies identified six years ago contributed to the alleged irregularities under investigation. If the recommendations had been acted upon promptly, observers say,

stronger internal controls might have reduced the risk of financial misconduct.

No final conclusions have yet been reached by the SIT, and the investigation is ongoing. The Trust has not publicly responded in detail to the latest reported findings.

The case has renewed calls for greater transparency, robust auditing, and stronger governance in the administration of major religious institutions that receive large public donations. As the investigation progresses, attention will remain focused on whether systemic lapses, rather than isolated misconduct, allowed the alleged irregularities to occur.

When Negligence Becomes a Killer

The tragic fire in Lucknow, which claimed the lives of several coaching students, is more than an accident—it is a shocking indictment of a system that repeatedly ignores public safety. Every major fire disaster is followed by compensation, arrests, and inquiry committees, yet little changes. The same lapses return, and innocent lives continue to be lost.

The real issue is accountability. Did

the building comply with fire safety norms? Were emergency exits available and functional? If violations existed for years, responsibility lies not only with the building owner but also with municipal authorities, fire departments, and officials who failed to enforce the law.

Across India, commercial buildings, coaching centres, hospitals, and malls often operate with inadequate safety measures while inspections remain weak or compromised. Human life cannot be sacrificed for profit or administrative negligence.

India does not need more promises after every tragedy—it needs strict enforcement before disasters occur. Mandatory safety audits, regular fire drills, severe penalties for violators, and personal accountability for negligent officials must become the norm.

A nation's progress is measured not by the compensation it pays after a disaster, but by its ability to prevent one. Until safety becomes non-negotiable, such tragedies will continue to expose the deadly cost of official apathy.

Can Rahul Gandhi Hold INDIA Together?

—Jan Jan Vichar

...Kamlesh

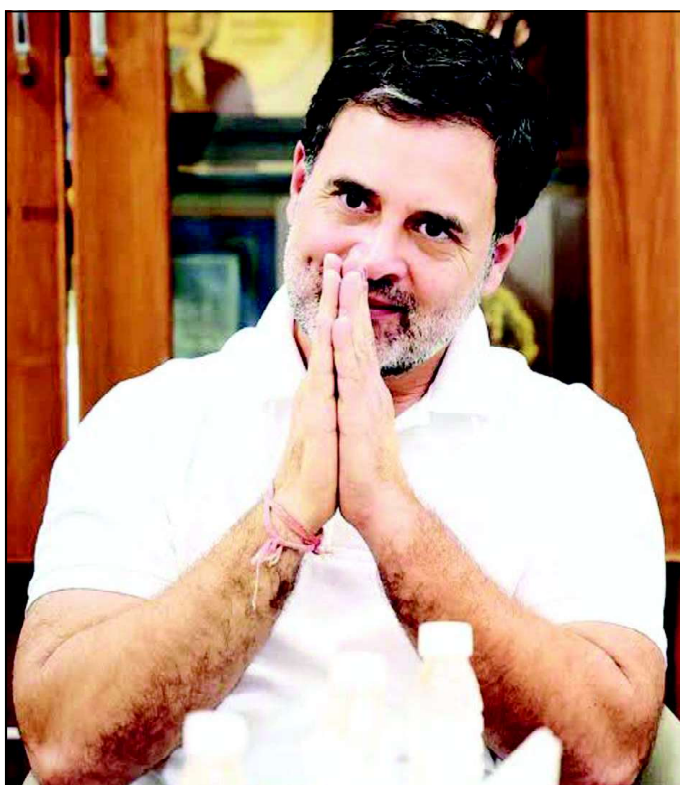
The political landscape ahead of the 2027 electoral cycle is witnessing another phase of realignment. Recent debates surrounding the strength of the INDIA alliance have once again raised an important question: Can Rahul Gandhi emerge as the consensus leader of a diverse opposition, or will powerful regional parties increasingly chart their own course?

The discussion gained momentum following political commentary suggesting that several opposition parties are reassessing their electoral strategies amid changing national equations. While such assessments remain speculative, they reflect a broader reality—coalition politics in India is entering a period of uncertainty.

The BJP-led National Democratic Alliance (NDA) appears determined to strengthen its parliamentary position after facing challenges in pushing certain legislation during previous sessions. Political observers believe that the government is actively working to build broader support for key bills, encouraging new political equations across party lines.

At the same time, reports of internal differences within opposition parties have added to questions about the future of the INDIA bloc. There have been discussions about growing distance between the Congress and the DMK, changing political calculations within the Trinamool Congress, and uncertainty surrounding the future strategy of Shiv Sena (UBT). However, many of these developments remain matters of political speculation, and the positions of the respective parties continue to evolve.

For Rahul Gandhi, the challenge is larger than leading the Congress.



At the same time, reports of internal differences within opposition parties have added to questions about the future of the INDIA bloc. There have been discussions about growing distance between the Congress and the DMK, changing political calculations within the Trinamool Congress, and uncertainty surrounding the future strategy of Shiv Sena (UBT).

He must convince influential regional leaders that the alliance is based on partnership rather than political dominance. Leaders such as Mamata Banerjee, Uddhav Thackeray, Sharad Pawar, M.K. Stalin, and others command significant regional support and have independent political priorities. Maintaining unity among such di-

verse partners requires constant dialogue, mutual respect, and a shared political vision.

Another challenge for the opposition is balancing national leadership with regional aspirations. In many states, regional parties enjoy stronger public support than the Congress. Any perception that one party seeks to dominate the alliance

may create friction, especially when seat-sharing and leadership questions arise before major elections.

Meanwhile, the NDA continues to benefit from a relatively cohesive leadership structure. With a clear central command and coordinated electoral strategy, the alliance has projected stability, which remains an important factor in Indian politics.

However, Indian politics has repeatedly demonstrated that alliances can change rapidly. Today's rivals may become tomorrow's partners, while today's allies may pursue independent paths depending on regional interests and electoral arithmetic. Coalition politics has always been dynamic, and no political equation can be considered permanent.

Ultimately, the future of the INDIA alliance will depend not merely on speeches or public meetings but on its ability to resolve internal differences, develop a common programme, and present a credible alternative to voters. Equally, the NDA will have to sustain its political momentum through governance, effective legislation, and continued public confidence.

The coming months will therefore be crucial. As Parliament prepares for future sessions and states move closer to important elections, both alliances face significant tests. Whether Rahul Gandhi succeeds in keeping the opposition united—or whether regional ambitions reshape India's political landscape once again—will be one of the defining stories of the country's next electoral chapter.

In Indian democracy, alliances are built not only on ideology but also on trust, accommodation, and electoral realities. Leadership is important, but coalition politics ultimately succeeds when every partner believes its voice matters.

Jan Jan Vichar
The Student's Corner
Board Exam Focus

Chemistry is everywhere—from the food we eat to the medicines we take. Understanding acids, bases and salts helps us understand the science behind daily life.

Acids, bases and salts are among the most important topics in Class X Science. They are not only essential for scoring well in the Board Examination but also help us understand many natural and industrial processes around us. Whether it is the sour taste of lemon, the antacid we take for stomach acidity, or the baking soda used in cakes, all are examples of the practical application of this chapter.

What are Acids?

Acids are substances that release hydrogen ions (H^+) when dissolved in water. They usually have a sour taste and can react with metals and carbonates. Acids turn blue litmus paper red, which is one of the simplest tests to identify them.

Common Examples:

Hydrochloric Acid (HCl)
 Sulphuric Acid (H_2SO_4)
 Nitric Acid (HNO_3)
 Acetic Acid (CH_3COOH) – found in vinegar
 Citric Acid – found in lemons and oranges

Strong acids ionise completely in water, while weak acids ionise only partially.

What are Bases?

Bases are substances that produce hydroxide ions (OH^-) in water. They generally have a bitter taste and a slippery or soapy feel. Bases turn red litmus paper blue.

Common Examples:

Sodium Hydroxide (NaOH)
 Potassium Hydroxide (KOH)
 Calcium Hydroxide [$Ca(OH)_2$]
 Magnesium Hydroxide [$Mg(OH)_2$]

Strong bases completely dissociate in water, whereas weak bases dissociate only partially.

Understanding Indicators

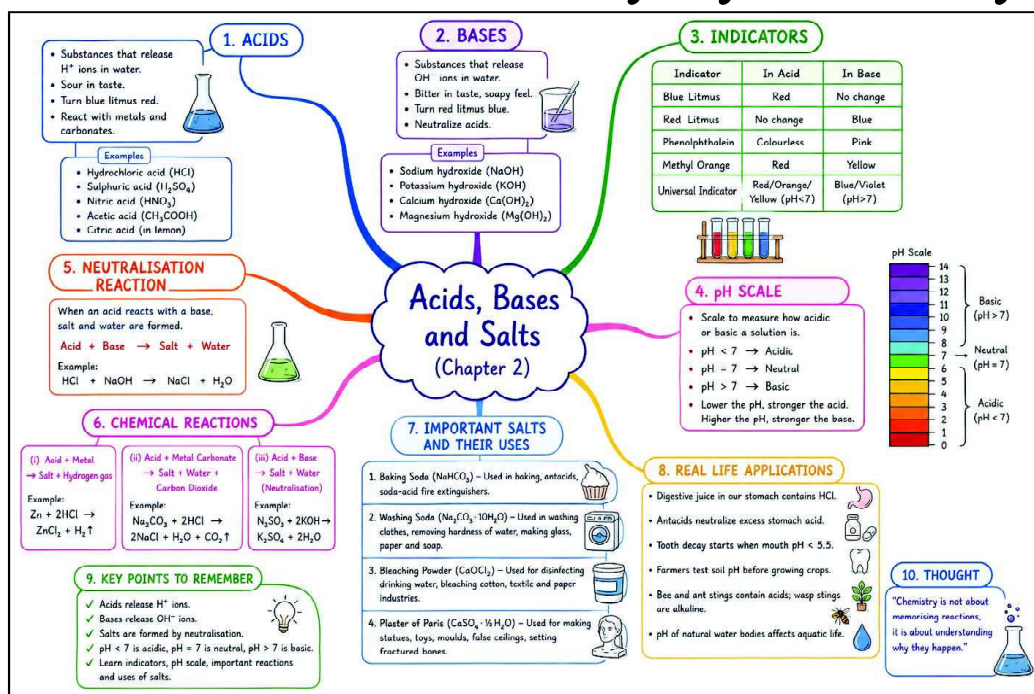
Indicators are chemicals that change colour depending on whether a solution is acidic or basic.

Indicator	Acid	Base
Blue Litmus	Turns Red	No Change
Red Litmus	No Change	Turns Blue
Phenolphthalein	Colourless	Pink
Methyl Orange	Yellow	
Universal Indicator	Red to Orange	Blue to Violet

The Universal Indicator gives a wide range of colours and helps determine the approximate pH value of a solution.

Acids, Bases and Salts

The Foundation of Everyday Chemistry



The pH Scale

The pH scale measures how acidic or basic a solution is.

pH below 7 – Acidic
 pH equal to 7 – Neutral
 pH above 7 – Basic

The lower the pH value, the stronger the acid. Similarly, the higher the pH value, the stronger the base.

Importance of pH in Daily Life

The pH scale has many practical applications:

Digestion: Our stomach secretes hydrochloric acid to digest food. Excess acid causes indigestion, which is treated using antacids.

Tooth Decay: When the pH in the mouth falls below 5.5, tooth enamel starts dissolving. Brushing with basic toothpaste helps prevent decay.

Agriculture: Farmers test soil pH before cultivating crops because different plants grow best in different pH conditions.

Animal and Insect Stings: Bee and ant stings contain acids,

while wasp stings are alkaline. Appropriate treatment depends on the nature of the sting.

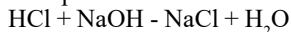
Environmental Protection:

The pH of lakes, rivers and rainwater affects aquatic life and agriculture.

Neutralisation Reaction

A neutralisation reaction occurs when an acid reacts with a base to produce salt and water, usually releasing heat.

Example:



This reaction has many applications, including the preparation of medicines and treatment of acidic soils.

Washing Soda ($Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$)

Used for washing clothes.
 Removes permanent hardness of water.

Used in the manufacture of glass, paper and soaps.

Bleaching Powder ($CaOCl_2$)

Disinfects drinking water.
 Bleaches cotton and linen.
 Used as a bleaching agent in paper industries.

Plaster of Paris ($CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$)

Used for making statues and toys.
 Used in hospitals for fractured bones.
 Used for decorative ceilings and moulds.

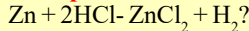
IMPORTANT CHEMICAL REACTIONS

Students should remember these three fundamental reactions:

1. Acid + Metal

Acid + Metal - Salt + Hydrogen Gas

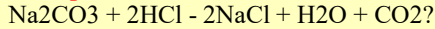
Example:



2. Acid + Metal Carbonate

Acid + Carbonate - Salt + Water + Carbon Dioxide

Example:



3. Acid + Base

Acid + Base - Salt + Water

This is called the Neutralisation Reaction.

Common Salts and Their Uses

Baking Soda ($NaHCO_3$)

Used in baking powder to make cakes soft and fluffy.

Used as an antacid.

Used in soda-acid fire extinguishers.

Important Activities

Board frequently asks questions based on practical activities. Students should revise the activities given in text book.

Tiny Wonders Beneath the Earth

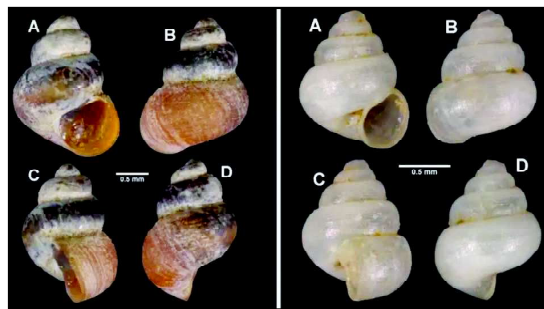
Meghalaya's Microscopic Snails Reveal Nature's Hidden Treasure

Jan Jan Vichar
...Guwahati

Deep beneath the lush hills of Meghalaya, where sunlight never reaches and silence dominates, scientists have uncovered two remarkable new species that remind us how much of nature still remains unexplored. The discovery of two microscopic cave-dwelling snails—*Georissa meghalayaensis* and *Acmella bensoni*—has added another chapter to Northeast India's extraordinary biodiversity story.

The newly discovered species, found inside the limestone cave systems of Krem Puri and Arwah, are so tiny that they can only be properly identified under a microscope. Yet, despite their size, they carry enormous scientific significance.

Researchers Nipu



Kumar Das and Neelavar Ananthram Aravind of the Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE) documented the discoveries, which were recently published in the European Journal of Taxonomy. Their work highlights the rich but poorly understood underground ecosystems of Meghalaya.

One of the species, *Georissa meghalayaensis*, was discovered near the entrance of Krem Puri

cave. It is instantly recognizable by its striking orangish-red shell decorated with intricate mesh-like ridges. Named after the state where it was found, the species appears to exist nowhere else in the world.

The second species, *Acmella bensoni*, was found deeper inside the caves. Its tiny translucent shell and delicate ribbed structure make it unique among India's cave snails. It was named in honour of

William H. Benson, the 19th-century naturalist regarded as one of the pioneers of Indian malacology—the scientific study of molluscs.

A Global Biodiversity Hotspot

Meghalaya lies within the Indo-Burma Biodiversity Hotspot, one of the world's richest ecological regions. With over 1,200 limestone caves, the state provides ideal habitats for specialised organisms that have evolved in complete darkness over thousands of years.

Scientists believe many more unknown species are waiting to be discovered in these underground worlds. Every expedition into these caves has the potential to reveal organisms found nowhere else on Earth.

Fragile Ecosystems Under Threat

The excitement of discovery comes with a serious warning.

Researchers caution that growing tourism inside popular caves could unintentionally damage these fragile ecosystems. Heavy foot traffic, artificial lighting, construction of stairways, and human disturbance may alter the delicate environmental conditions required for these tiny creatures to survive.

Limestone mining poses an even greater threat. Since these snails depend entirely on limestone cave habitats, mining activities could permanently destroy ecosystems that took millions of years to evolve.

Unlike larger animals, microscopic cave species often go unnoticed, making conservation even more challenging.

Don't Marry Indian Men

Jan Jan Vichar
...Lifestyle Desk

Every few weeks, social media discovers a new relationship controversy. One month it is 'red flags' in dating. The next, it is debates over feminism, marriage, masculinity, or family expectations. The latest storm erupted after a relationship coach's viral statement advising women not to marry Indian men.

Predictably, the internet exploded. Supporters called it an uncomfortable truth, while critics condemned it as a sweeping stereotype.

But beneath the outrage lies a more important question: Why are relationship debates becoming India's



favourite online battleground?

The answer lies in a society undergoing rapid transformation. Today's young Indians are more educated, financially independent, and digitally connected than any previous generation. Traditional expectations about marriage, gender roles, and family responsibilities are being chal-

lenged by new ideas about equality, personal freedom, and emotional compatibility.

Social media amplifies these tensions. Platforms reward strong opinions, not nuanced discussions. A controversial statement can generate millions of views within hours, turning complex social issues into binary choices—right or wrong, progressive or regressive. As a result, genuine conversations about relationships often become shout-out matches.

At the same time, changing aspirations are reshaping the institution of marriage itself. Many young people now prioritize emotional connection, mutual respect, and personal growth over social ap-

D.S. ASSOCIATES
TAX CONSULTANTS

TRUSTED ADVISORS

ONE-STOP SOLUTION

ALL YOUR TAX & FINANCE NEEDS UNDER ONE ROOF

Expert, reliable and timely solutions for individuals, businesses & startups — handled by experienced professionals you can trust.

OUR SERVICES

- Income Tax Returns
- Audit
- Loans
- Company Registration
- Trademark Registration
- Subsidy Related Works

- GST Registration & Filing
- Accounting & Book Keeping
- Insurance
- Import & Export Compliance
- FSSAI Registration
- Documentation Services

...AND MANY MORE SERVICES

CALL US TODAY

Mohan Choudhary
70026 82705

Subhash Choudhary
84728 20656

Email : dssalestax@gmail.com